सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

सु-विचार

" वक्त जब जवाब देता है
तब सफाई देने की जरूरत नहीं होती...!! "

अज्ञात...

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

वर्ष–01 अंक–177 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, गुरुवार 16 जुलाई 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

विश्व पॉवर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों का दुर्ग स्टेशन में हुआ स्वागत

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग-भिलाई

विश्व पॉवर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप दक्षिण आफ्रीका में आयोजित थी। इस चैम्पियनशिप में भारत से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जयदीप साहू, प्रियांक मिश्रा, अमान शुक्ला ने हिस्सा लिया। भारतीय टीम के साथ उनका कोच कृष्णा साहू भी दक्षिण आफ्रीका में 4 जुलाई से 12 जुलाई तक आयोजित विश्व स्तरीय एशिया–पेसिफिक अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष पॉवर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी प्रियांक मिश्रा ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए उन्होंने स्वर्ण एवं कांस्य दोनों पदक जीताकर देश का नाम विश्व पटल पर गौरांवित किया।

इसी तरह जयदीप साहू, अमान शुक्ला ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की –ोली स्वर्ण पदक से भर दिया। विश्व पॉवर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर उनकी भारत वापसी हुई। आज शाम दुर्ग रेलवे स्टेशन में खिलाड़ी और पॉवर लिफ्टिंग कोच कृष्णा साहू का भिलाई दुर्ग के खेल प्रेमियों ने बाजे–गाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। फूलमालाओं से खिलाड़ी और कोच को खेल प्रेमियों ने लाद दिया। पॉवर लिफ्टिंग के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए

एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक जी सुरेश बाबे, इन्द्रजीत सिंह छोटू और सीजीपीएलए के अध्यक्ष कैलाश जैन बरमेचा ने बधाई दी। खिलाड़ियों ने सभी पदाधिकारियों को मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

खिलाड़ियों ने बिलासपुर के सहयोगियों एवं विशेषकर छग शासन का भी आर्थिक सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रियांक मिश्रा, जयदीप साहू और अमान शुक्ला ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय भारतीय टीम के कोच कृष्णा साहू को देते हुए बताया कि उन्होंने हमें निरंतर प्रेरणा दी। प्रियांक मिश्रा ने भी अपने निजी कोच आसिफ अली व भारतीय टीम के कोच कृष्णा साहू का आभार व्यक्त किया है। खिलाड़ियों के आगमन पर दुर्ग स्टेशन में दुर्ग–भिलाई के खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उमड़े। बाजे–गाजे के साथ खिलाड़ियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया।

SFI का आरोप : निजी विवि के लिए भूमि की अनिवार्यता हटाना

शिक्षा माफियाओं को संरक्षण

"छत्तीसगढ़ बना बिना जमीन के विश्वविद्यालय खोलने वाला देश का पहला राज्य"

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

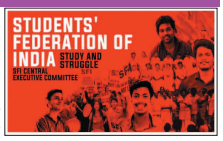

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने विधानसभा में निजी विश्वविद्यालयों के लिए न्यूनतम भूमि की अनिवार्यता समाप्त करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है। SFI ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह शिक्षा माफियाओं और दलालों की गिरफ्त में है।

SFI के जिलाध्यक्ष गर्व गभने, जिलासचिव हर्ष संघाणी और उपाध्यक्ष अल्पिका कन्नौजे ने जारी बयान में कहा कि राज्य शासन के संरक्षण में निजी विश्वविद्यालय धन्नासेठों और नेताओं की "निकम्मी औलादों" को फर्जी डिग्री बांट रहे हैं। शिकायत के बाद भी विनियामक आयोग और उच्च शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उल्टे शिकायतकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। जांच के नाम पर दलाल अधिकारियों और प्रोफेसरों की कमेटी बनाकर वसूली की जा रही है।

"नए कॉलेज और स्कूल के लिए जमीन जरूरी, विवि के लिए नहीं"

नेताओं ने कहा कि कल विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर निजी विश्वविद्यालयों के लिए न्यूनतम भूमि का प्रावधान खत्म कर दिया गया। अब राज्य में नया कॉलेज और स्कूल खोलने के लिए जमीन जरूरी है, लेकिन निजी विश्वविद्यालय एक इंच जमीन के बिना भी स्थापित हो सकता है।

SFI ने UGC के 2023 के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि नए कॉलेज के लिए महानगर में 2 एकड़ और अन्य क्षेत्रों में 5 एकड़ जमीन अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम में भी अधिकांश जिलों के लिए 5 एकड़ का मानदंड है।

देश में सबसे अलग छत्तीसगढ़

SFI के अनुसार देश के किसी भी राज्य में बिना भूमि के निजी विश्वविद्यालय खोलने का नियम नहीं है। अन्य राज्यों में न्यूनतम भूमि इस प्रकार है:–

आंध्र प्रदेश 50 एकड़, अरुणाचल 50 एकड़, असम 10–20 एकड़, बिहार 5–10 एकड़, गुजरात 30 एकड़, हरियाणा 10–20 एकड़, झारखंड 10–25 एकड़, कर्नाटक 25–50 एकड़, मध्य प्रदेश 50 एकड़, महाराष्ट्र 20 एकड़, ओडिशा 25 एकड़, पंजाब 35 एकड़, राजस्थान 30 एकड़, उत्तर प्रदेश 20–50 एकड़, उत्तराखंड 25 एकड़। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब यह सीमा "शून्य एकड़" कर दी गई है।

SFI ने कहा कि 2003 में भाजपा ने तत्कालीन अजीत जोगी सरकार में खुले निजी विवि को "2 कमरे की यूनिवर्सिटी" कहकर विरोध किया था। अब खुद उसी तरह "2 कमरे की यूनिवर्सिटी" बनाने का रास्ता खोल रही है। **मांग :** SFI ने प्रस्ताव तुरंत वापस लेने और विनियामक आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की मांग की है।

बांकीपुर उपचुनाव : PK की एंट्री से हिली बीजेपी की नींव? 30 साल पुराने गढ़ में त्रिकोणीय जंग

बिना बेस वोट के किंगमेकर ने ठोकी ताल, सवर्ण नाराजगी और एंटी–इंकंबेंसी बनेगा टर्निंग पॉइंट?

आलोक तिवारी / पटना

बिहार की सबसे वर्चित सीट पटना की बांकीपुर में इस बार उपचुनाव ने राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान खींच लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर नामांकन और स्क्रूटनी के बाद तस्वीर साफ हो गई है। मैदान में कई चेहरे हैं, लेकिन असली मुकाबला त्रिकोणीय है। इस बार बांकीपुर की जंग इसलिए सबसे ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर पहली बार खुद विधायक बनने के लिए मैदान में हैं।

मैदान के तीन योद्धा

1. प्रशांत किशोर - जन सुराज: देश भर में सरकारें बनवाने वाले PK अब खुद उम्मीदवार हैं। उनके पास न कैडर है न बेस वोट, लेकिन सर्वे और रणनीति उनके सबसे बड़े हथियार हैं।

2. नीरज सिन्हा - BJP: बीजेपी ने इस अभेद्य सीट पर कोई बड़ा नाम उतारने के बजाय जमीनी कार्यकर्ता नीरज सिन्हा पर भरोसा जताया है।

3. रेखा गुप्ता - RJD: RJD ने अनुभवी चेहरा रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है।

1995 से बीजेपी का किला

बांकीपुर 1995 से लगातार बीजेपी का गढ़ रहा है। यहां लोकसभा हो या विधानसभा, बीजेपी उम्मीदवारों को 50% से 80% तक वोट मिलते रहे हैं। अभी बिहार में भी इखड–नीत सरकार है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। ऐसे में इस सीट को बीजेपी के लिए आसान माना जा रहा था। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री ने समीकरण बदल दिए हैं। नितिन नवीन खुद पटना में कैंप कर रणनीतिकारों के साथ बैठकें कर रहे हैं।

PK का गणित : बेस वोट नहीं, नाराजगी है

प्रशांत किशोर के पास बीजेपी–आरजेडी जैसा जातीय कैडर नहीं है। उनकी नजर बीजेपी के एक खास वर्ग की "दबी हुई नाराजगी" पर है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भरत तिवारी एनकाउंटर और UGC विवाद जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी का पारंपरिक सवर्ण वोटर – भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत – अंदरखाने नाराज है। PK इसी एंटी–इंकंबेंसी को भुनाने की कोशिश में हैं।

बांकीपुर का जातीय कैलकुलेशन

बांकीपुर में जीत–हार जातीय समीकरण से ही तय होती है: कायस्थ: सबसे बड़ी आबादी। बीजेपी का कोर वोटर। सवर्ण: भूमिहार + राजपूत + ब्राह्मण + कायस्थ = लगभग 35%। यहीं असली खेल है। RJD का कोर: मुस्लिम 10%, यादव 10%। इसके अलावा वैश्य और दलित वोट भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

किसके सिर सजेगा ताज?: फिलहाल कैडर और संगठन के आधार पर बीजेपी को स्पष्ट बढ़त है। विश्लेषकों का मानना है कि जब तक RJD का MY समीकरण नहीं टूटता या बीजेपी के कोर सवर्ण वोट में बड़ी सेंध नहीं लगती, बीजेपी के किले को हिलाना मुश्किल है। PK की सबसे बड़ी चुनौती है "बेस वोट" बनाना। अगर वे प्रचार के दौरान बीजेपी और RJD दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं तो मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। नामांकन वापसी और अब शुरू होने वाले धुआंधार प्रचार के बाद ही साफ होगा कि 30 साल पुराने इस किले को PK ढहा पाते हैं या बीजेपी एक बार फिर अपना परचम लहराती है।

दुर्ग में वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए खुलेगा विशेष न्यायालय

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

मंत्री गजेंद्र यादव की पहल, समयबद्ध सुनवाई से व्यापारियों को मिलेगी राहत

जिले के उद्यमियों और व्यापारियों को वाणिज्यिक विवादों में त्वरित न्याय मिलेगा। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव की पहल पर दुर्ग में वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

विधि एवं विधायी कार्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक द्वितीय सिविल जज सीनियर डिवीजन दुर्ग के न्यायालय में होने वाली वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई अब चतुर्थ सिविल जज सीनियर डिवीजन दुर्ग के न्यायालय में होगी। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 3 के तहत उक्त न्यायालय को सिविल जज स्तर के विशेष वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में नामित करने की अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।

व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

इस निर्णय से जिले से जुड़े वाणिज्यिक विवादों का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण हो सकेगा। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने से व्यापारियों को त्वरित राहत मिलेगी। साथ ही जिले के औद्योगिक और व्यावसायिक वातावरण को मजबूती मिलेगी और नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि विशेष न्यायालय की स्थापना से दुर्ग के उद्यमियों, व्यापारियों और उद्योगों को लंबित मामलों से मुक्ति मिलेगी और व्यवसाय करने में आसानी होगी।

'सरस्वती साइकिल योजना' की साइकिलें खुले में जंग खा रही, छात्राओं का सपना टूटने की कगार पर

900 में से 300 साइकिलें असेंबल, बारिश में भीग रहे पुर्जे ; कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी 'सरस्वती साइकिल योजना' के तहत छात्राओं को मिलनी वाली साइकिलें बेमेतरा ब्लॉक में खुले आसमान के नीचे बेकार हो रही हैं। नई चमचमाती साइकिलों की जगह परिसर में लोहे के फ्रेम, पहिए और प्लास्टिक में लिपटे टायरों का ढेर लगा है, जिसे देखकर कोई भी इसे कबाड़ी की दुकान समझ सकता है।

मौसम के बदलते मिजाज और लगातार हो रही बारिश के कारण खुले में पड़े लोहे के पार्ट्स में जंग लगने का खतरा बढ़ गया है। पानी में भीगने से साइकिलों की मजबूती और उम्र पर सीधा असर पड़ने की आशंका है।

असेंबली का काम कर रहे एक युवक ने बताया कि पिछले 15 दिनों से यह कार्य चल रहा है। अब तक 300 साइकिलें तैयार की जा चुकी हैं, जबकि कुल 900 साइकिलें असेंबल करनी हैं।

कलेक्टर ने दिए निर्देश

इस मामले में बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगोई ने कहा कि यह मामला संज्ञान में लाया गया है। निश्चित रूप से जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी साइकिलों की असेंबली को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी, बीईओ, बीआरसी और प्राचार्यों को निर्देशित किया गया था कि वे अपने निगरानी में असेंबली का काम कराएं।

सरस्वती साइकिल योजना के तहत बेटियों को स्कूल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए साइकिलें दी जाती हैं। लेकिन असेंबली और रखरखाव में लापरवाही के कारण योजना की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों और शिक्षकों ने मांग की है कि शेष साइकिलों को जल्द से जल्द ढके हुए स्थान पर रखा जाए और असेंबली में तेजी लाई जाए, ताकि छात्राओं को समय पर साइकिलें मिल सकें।

17 अगस्त को निकलेगी विशाल बोल बम कांवर यात्रा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को समिति ने दिया आमंत्रण

नई दृष्टिबिंदु / पाटन

बोल बम कांवर यात्रा समिति पाटन के संयोजक और भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को 17 अगस्त को आयोजित होने वाली विशाल बोल बम कांवर यात्रा महोत्सव में आमंत्रित किया। जितेन्द्र वर्मा ने विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री से सौजन्य भेंट कर यात्रा की रूपरेखा और तैयारियों से अवगत कराया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव भी उपस्थित थे।

श्री वर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन के तीसरे सोमवार को पाटन से टोलाघाट तक हजारों शिवभक्तों की सहभागिता से भव्य कांवर यात्रा निकाली जाएगी। श्रद्धालु "बोल बम" के जयघोष के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पैदल यात्रा करेंगे।

सेवा और समरसता का प्रतीक

जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि बोल बम कांवर यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता, सेवा और जनआस्था का विराट उत्सव है। यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए चिकित्सा, पेयजल, भोजन, विश्राम, सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता की समुचित व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आमंत्रण सहर्ष स्वीकार करते हुए समिति को आयोजन की शुभकामनाएं दीं।

समिति ने क्षेत्र के श्रद्धालुओं, सामाजिक और धार्मिक संगठनों, युवा मंडलों, महिला समूहों और जनप्रतिनिधियों से 17 अगस्त को पाटन से टोलाघाट तक निकलने वाली इस यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होकर इसे ऐतिहासिक बनाने की अपील की है।

खेत में बने तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत, गांव में मातम

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

जिले के डोंगरगढ़ अंतर्गत बोरतालाब क्षेत्र में खेत समतलीकरण के दौरान बने गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से तीन मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है और पीड़ित परिवारों का रो–रोकर बुरा हाल है। मृतकों में दो सगे भाई भी शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार बोरतालाब क्षेत्र के एक खेत में कुछ दिन पहले समतलीकरण का काम हुआ था। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण इस गड्ढे में काफी पानी भर गया था। बुधवार को गांव के तीन बच्चे खेलते–खेलते खेत की तरफ चले गए। बच्चों को अंदाजा नहीं था कि पानी से भरा यह गड्ढा उनके लिए जानलेवा साबित होगा। खेलते समय तीनों गहरे पानी में चले गए और एक–दूसरे को बचाने के प्रयास में सभी डूब गए। काफी देर तक बच्चों के घर नहीं लौटने पर जिजनों ने खोजबीन शुरू की। ग्रामीणों को खेत के पास बच्चों के कपड़े और चप्पलें मिलीं। इसके बाद पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। रात का अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आईं। ग्रामीणों और प्रशासन की टीम ने टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में मशक्कत कर पानी से तीनों बच्चों के शव बाहर निकाले। शव देखकर मौके पर चीख–पुकार मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दान की राशि की चोरी, जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई ने किया मौन प्रदर्शन

भगवान श्री हनुमान को अर्जी देकर दोषियों को दंडित करने की मांग, सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं इसलिए भगवान, श्री हनुमान को लगाई अर्जी : मुकेश चंद्राकर

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में हुई दान की राशि की चोरी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई ने मंगलवार, 14 जुलाई को सेक्टर 9 स्थित मेन हॉस्पिटल स्थित हनुमान मंदिर के समक्ष मौन प्रदर्शन किया। साथ ही मंदिर के पंडितों के माध्यम से भगवान श्री हनुमान जी को अर्जी देकर चोरों को कर्मानुसार फल देने की मांग की।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में शाम 5 बजे कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सैकड़ो की संख्या में मंदिर परिसर पहुंच गए। सभी ने मुंह पर काली पट्टी बांध रखी थी। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधायक बी डी कुरैशी, महापौर नीरज पाल, पूर्व महापौर सुश्री नीति लोधी, जितेंद्र साहू, बृजमोहन सिंह, अतुल साहू, सीजू एंथोनी, संदीप निरंकारी सहित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

आधे घंटे मौन रखने के पश्चात पंडित घटोत्कच शुक्ला सहित अन्य ब्राह्मण भाइयों के माध्यम से मंदिर के भीतर पहुंच कर भगवान श्री हनुमान जी को अर्जी सौंपी गई। इस अवसर पर अध्यक्ष श्री चंद्राकर ने कहा कि राम मंदिर से दान और चढ़ावे की जिस तरह चोरी हुई है वह शर्मनाक है। केंद्र में बैठी सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में न्याय की उम्मीद किससे करें। यही कारण है कि ब्राह्मण भाइयों की मदद से भगवान श्री हनुमान जी को अर्जी दी जा रही है ताकि वही न्याय करें और दोषियों को दंडित करें।

इस अवसर पर पूर्व गृहमंत्री ताम्रकार साहू ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। कारवाई के नाम पर छोटे लोगों को दोषी बना दिया गया है जबकि असली जिम्मेदार बच निकले हैं। दोषियों

की पहचान हो और उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिले इसलिए कांग्रेस ने आज यह प्रदर्शन किया है।

अर्जी में लिखा है....

जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई ने भगवान श्री हनुमान जी को दिए गए अर्जी में सादर प्रणाम करते हुए लिखा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के चरणों में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु श्रद्धा आस्था के साथ लाखों रुपए का दान करते हैं। यह केवल धन नहीं बल्कि सनातनियों की भावनाओं का प्रसाद है। लेकिन कुछ लालची लोगों ने इस पवित्र दान की चोरी कर ली है और लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचाई है। आपसे अनुरोध है कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें और कर्मों के अनुसार उन्हें दंड दें ताकि धर्म की रक्षा हो सके और लोगों की आस्था बनी रहे।

इनकी उपस्थिति रही...

नरसिंह नाथ, जी राजू, दिनेश पटेल, सौरभ दत्ता, सौरभ मिश्रा, मोहम्मद रफीक, भूपेंद्र यादव, सुभद्रा सिंघ,राजेश साहू, लालचंद वर्मा, प्रभाकर जनवंधु, इमरान अंसारी, संगीता सिंह, राजेश चौधरी, शमशेर सिद्दीकी, निरंजन बिसाई, आनंद डोंगरे, सुजीत कुमार, नंद कुमार कश्यप, मेरिक सिंग, केशव चौबे,रविंदर सिंह, हीरा शंकर साहू, जावेद खान, रवि शर्मा, अली हुसैन सिद्दीकी, चुम्मन देशमुख,डी नारायण, नेहा साहू, शिखा रॉय, दुर्गेश ताम्रकार, राजकुमार देशमुख, जितेश बंजारे, साकेत चंद्राकर,दीपक भाटिया, अनुसूइया मरकाम, प्रमोद प्रभाकर, कीर्ति सिंह,अरविंद ताम्रकार, छगन साहू, सुशील साहू, राजेश्वर प्रसाद, द्वारका साहू, बुद्धशरण बोरकर, उमा शंकर साहू, अजय यादव, शिव साहू विष्णु बारले, बजरंगी, अनमोल पवन चौबे, विनोद गुप्ता, विक्की शर्मा, गोविंद कोसले, योगेश राव, सलमान, राजेश यादव,अमन साहू, संतु मानिकपुरी, उत्तम देशलेरे राजू साहू, बबीता मानिकपुरी, अनिल सिंह, शेख अकरम, मनीष शुक्ला, अरविंद राय, महेन्द्र साहू, घटोत्कच शुक्ला, नरेन्द्र पीपरोल, राहुल सिंह, अमित सिंह, नरेश सगरवंशी, गौरव श्रीवास्तव शाहिद सैकड़ो की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

खास खबर

एसएमएस-3 में महिला संविदा कर्मियों के लिए नई चेतना कार्यक्रम का हुआ आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के इस्पात गलन शाला-3 (एसएमएस-3) के कॉन्फ्रेंस हॉल में महिला संविदा कर्मियों के लिए नई चेतना जागरूकता एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला संविदा कर्मियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा, महिला अधिकारों, औद्योगिक संबंध, श्रमिक कल्याण योजनाओं, मातृत्व संबंधी सुविधाओं और स्वास्थ्य एवं उत्पीड़न से जुड़े विषयों के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य महाप्रबंधक (एसएमएस-3) त्रिभुवन बैठा के संबोधन से हुआ। उन्होंने महिला कर्मियों को सुरक्षित कार्य संस्कृति अपनाने, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहने तथा आत्मविश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जागरूक और सशक्त महिला कर्मी किसी भी संगठन की कार्य संस्कृति को सुरक्षित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कार्यक्रम की मुख्य जानकारी: विभागीय सुरक्षा अधिकारी उमाशंकर परगनिहा ने कार्यस्थल सुरक्षा और महिला सुरक्षा के उपाय बताए और सुरक्षित कार्य व्यवहार अपनाने पर बल दिया। औद्योगिक संबंध विभाग के राजेश मौर्य ने न्यूनतम वेतन, श्रमिक कल्याण योजनाओं और औद्योगिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। ऑक्युपेशनल हेल्थ सेंटर की शुभश्री प्रशांत ने महिलाओं के स्वास्थ्य, मातृत्व सुविधाओं और स्वास्थ्य जागरूकता पर उपयोगी जानकारी साझा की।

कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। सही उत्तर देने वाली प्रतिभागियों को टोकन गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। नई चेतना कार्यक्रम में लगभग 50 से 60 महिला संविदा कर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम ने महिला सुरक्षा, जागरूकता और श्रमिक कल्याण संबंधी विषयों पर उनकी समझ को मजबूत किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक महाप्रबंधक (मानव संसाधन) सुशील कामड़े और विभागीय सुरक्षा अधिकारी उमाशंकर परगनिहा ने किया।

कदम संस्था ने लगाया 51 पौधों का वृहद वृक्षारोपण, महापौर अलका बागमार बोलीं- "हरियाली ही भविष्य"

दुर्ग। पर्यावरण संरक्षण और "हरित दुर्ग" के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कदम संस्था द्वारा बुधवार को शहर में 51 पौधों का वृहद वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम संस्था के अध्यक्ष प्रभु दयाल उजाला के व्यावसायिक परिसर के 50 वर्ष पूर्ण होने और संस्था के एक सदस्य के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। कदम संस्था जनवरी 2025 से अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से वृक्षारोपण अभियान चला रही है। इसी कड़ी में आज विभिन्न प्रजातियों के 51 पौधे रोपे गए। साथ ही सभी पौधों के संरक्षण और नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया गया।

महापौर ने की सराहना: कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दुर्ग नगर पालिका निगम की महापौर एवं नगर की प्रथम नागरिक श्रीमती अलका बागमार रहीं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के दौर में इस तरह के जनसहभागिता आधारित अभियान समय की जरूरत हैं। महापौर ने कदम संस्था के निरंतर और अनुशासित प्रयासों की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए अधिक से अधिक लोगों से वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त उपवन मंडल अधिकारी अब्दुल वहिद खान, प्रसिद्ध समाजसेवी कैलाश जैन बरमेचा और डॉ. विजय कुमार गुप्ता सहित कई गणमान्य नागरिक और समाजसेवी उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने संस्था के अभियान की सराहना की। कार्यक्रम में कदम संस्था के सभी सदस्यों ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाई और पौधे लगाए। कार्यक्रम के अंत में संस्था अध्यक्ष प्रभु दयाल उजाला ने सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कदम संस्था आगे भी पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और जनहित के कार्यों को इसी निरंतरता के साथ आगे बढ़ाती रहेगी।

रोचक इतिहास बताने के साथ भविष्य की चिंता भी रखती है 'भिलाई जिंदाबाद' : बंछोर

भिलाई एक परिवार की तरह, इसे तोड़ने वालों को सफल नहीं होने देंगे

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

प्रगतिशील जन-विचारधारा की साहित्यिक संस्था 'आरंभ' के तत्वावधान में लेखक-पत्रकार मुहम्मद जाकिर हुसैन की पुस्तक 'भिलाई जिंदाबाद कुछ किस्से-कुछ कहानियां' पर चर्चा-विचार गोष्ठी भिलाई निवास के इंडियन कॉफी हाउस सभागार में आयोजित की गई। प्रारंभ में संध्या सातकर ने सरस्वती वंदना की। इसके उपरांत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वागत उद्बोधन 'आरंभ' के अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य एवं आयोजकीय वक्तव्य संयोजक शौकत इकबाल ने दिया।

इस मौके पर मुख्य अतिथि बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया (सेफी) के चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोर ने कहा कि लेखक मुहम्मद जाकिर हुसैन ने अपनी इस किताब में न केवल भिलाई का इतिहास रोचक ढंग से बताया है बल्कि भिलाई के भविष्य को लेकर गहन चिंता भी व्यक्त की है।

उन्होंने भिलाई के समक्ष आ रही चुनौतियों का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि आज ऐसी परिस्थिति निर्मित की जा रही है कि किसी न किसी तरह भिलाई को निजीकरण की तरफ मोड़ दिया जाए। 2004 में ऐसा प्रयास किया गया था। लेकिन भिलाई की जनता की खासियत है कि अपनी एकजुटता से इसे नाकाम करती रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीएसपी ओए और सेफी की तरफ ऐसी किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाएगा। अपनी बात रखते हुए उन्होंने बताया कि सेक्टर-9 अस्पताल को लेकर भिलाई वासियों की चिंता जायज है। इसके लिए हमने (ओए-सेफी) प्रस्ताव दिया है मैनेजमेंट भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि हृदय, किडनी और न्यूरो जैसे विभाग के लिए किसी संस्थान से अनुबंध कर यहां अलग से भवन दिया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर सभी को लाभ मिले।

टाउनशिप के संबंध में उन्होंने बताया कि उपर से यह दबाव जरूर है कि पब्लिक सेक्टर के पास जितनी भी जमीन है उसका मौद्रीकरण किया जाए और जितने पुराने मकान है, उन्हें गिराकर वह जगह किसी फर्म को दी जाए।

इसके लिए ओए-सेफी का प्रस्ताव है कि एनबीसीसी या हाउसिंग बोर्ड जैसे किसी सरकारी उपक्रम को टाउनशिप में ऐसी खाली जगह दी जाए, जहां आवास गिराए जा चुके हैं और अवैध कब्जे हो रहे हैं। जिससे वहां तालपुरी की तरह कालोनी विकसित की जाए और पूरा टाउनशिप उजाड़ने की नौबत न आए। उन्होंने कहा कि भिलाईवासी अपने आप को एक परिवार की तरह मानते हैं और इस परिवार को जो लोग भी तोड़ने का प्रयास करेंगे हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे।

इसके पहले लेखक मुहम्मद जाकिर हुसैन ने अपने लेखकीय वक्तव्य में कहा कि- मौजूदा दौर में सार्वजनिक उपक्रम कई तरह की चुनौतियों से रुबरु हो रहे हैं। अब जबकि पूरा परिवेश ही बदल रहा है तो ऐसे में पाठकों को 'भिलाई जिंदाबाद' सौंपते हुए कई सवाल मन में उठ रहे हैं कि क्या भिलाई अपने वजूद को बचा पाएगा?

वहीं आधार वक्तव्य रखते हुए युवा पत्रकार व कवि निलेश त्रिपाठी ने कहा कि उनकी तरह तमाम लोग भिलाई को जानते जरूर हैं लेकिन भिलाई को पहचानना है, इस शहर को समझना है तो आपको 'भिलाई जिंदाबाद' जरूर पढ़ना होगा।

विशिष्ट अतिथि सुस्थापित व्यंग्यकार विनोद साव ने किताब में लेखक की दादी मरहूमा फातिमा बी को समर्पित वाक्य 'आपने बीएसपी सेक्टर-1 अस्पताल के किचन में कोयले की भट्टी के सामने बरसों अपना खून जलाते हुए भरे-पूरे कुनबे को ठंडी छांव दी' से अपनी बात रखते हुए मैत्री बाग, सेक्टर-9 हॉस्पिटल का जिक्र किया एवं कल और आज के परिदृश्य को बताया।

विशिष्ट अतिथि स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. हंसा शुक्ला ने अपने विचार रखते हुए कहा कि लेखक ने भिलाई का इतिहास बेहद रोचक ढंग से रखा है और इसे हर भिलाईवासी को जरूर पढ़ना चाहिए।

चर्चा गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे 'आरंभ' के मुख्य सलाहकार आचार्य डॉ.महेशचंद्र शर्मा ने कहा कि-विश्व के मानचित्र में 'भिलाई' की अपनी एक पहचान है। आज भिलाई की संस्कृति और भिलाई स्टील प्लांट के सार्वजनिक उपक्रम के स्वरूप को बचाए रखने की जरूरत है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय किताब 'भिलाई जिंदाबाद' की महत्ता और बढ़ जाती है। आयोजन में संस्था 'आरंभ' की तरफ से कृतिकार मुहम्मद जाकिर हुसैन को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। अंत में उपस्थित सभी सदस्यों ने भिलाई इस्पात संयंत्र से सेवानिवृत्त प्रख्यात पंडवानी गुरु पद्म विभूषण स्व. तीजन बाई को दो मिनट की मौन श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर आलोक कुमार चंदा, दीप्ति श्रीवास्तव, शानू मोहनन, ठाकुर दशरथ सिंह भुवाल सोनपांडर, शेफाली भट्टाचार्य, संध्या सातकर, राकेश गुप्ता 'रसिया', सुशील यादव, डॉ. विजय कुमार गुप्ता 'मुन्ना', ब्रजेश मलिक, तारकनाथ चौधुरी, डॉ. नौशाद अहमद सिद्दीकी 'सब्र', हाजी रियाज खान गौहर, टीए खान, जाविद हसन 'भाईजान', ओमप्रकाश शर्मा, शुभेंदु बागची, हरि प्रकाश गुप्ता 'सरल', नागेंद्र साहू, मो. तारिक, सोनिया नायडू, शिव मंगल सिंह, शमशीर सिवानी, घनश्याम कुमार देवांगन और 'आरंभ' के अनेक सदस्य उपस्थित हुए. संचालन महासचिव नुरूस्सबाह खान 'सबा' एवं आभार प्रदर्शन वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्र्यम्बक राव साटकर 'अंबर' ने किया। 'आरंभ' के प्रवक्ता जाविद हसन 'भाईजान' और मीडिया प्रभारी डॉ.नौशाद अहमद सिद्दीकी'सब्र'ने यह जानकारी दी।

"गुंजन" ने विमल राय को दी सांगीतिक श्रद्धांजलि

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

इस्पात नगरी की संगीतधर्मी संस्था 'गुंजन' की ओर से फिल्म निर्माता निर्देशक विमल राय के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों के बांग्ला संगीतकार, सलिल चौधरी, सचिन देव बर्मन, हेमन्त कुमार एवं पार्श्वगायक मन्ना डे व गीता दत्त इत्यादि के कुछ कालजयी गीत प्रस्तुत करने एक सांगीतिक कार्यक्रम गुंजन हाउस रशियन कॉम्प्लेक्स सेक्टर-7 में आयोजित किया।

उल्लेखनीय है कि संस्था 'गुंजन' की ओर से पिछले 25 वर्षों से हिन्दी फिल्म संगीत के दिवंगत कलाकारों की जन्मतिथि और पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप बैठकें, मंचस्थ आयोजन और फेसबुक लाइव कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते रहे है।

इसी श्रृंखला में विमल राय की प्रसिद्ध फिल्मों देवदास, दो बीघा जमीन, मधुमती, सुजाता और बंदिनी पर आधारित फिल्मों के 12 कालजयी गीत डॉ. अनंत केकरे, अनुराधा तैलंग, अतुल तैलंग, तिलक धर दुबे, भास्वति बोस, मीना गुप्ता, शांतारम वानखेड़े, गीता सोनी, गिरीश चतुर्वेदी, गीता साठे, रूमा और सोमा बहनों प्रस्तुत किये। विमल राय के अलावा स्व. गुरूदत्त को भी उनकी प्यासा और साहब बीबी और गुलाम फिल्मों के लिए याद किया गया।

कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कवि शरद कोकास ने किया। आयोजन की मुख्य विशेषता यह थी कि सभी गीत कम से कम वाद्य यंत्रों पर बिना किसी ट्रैक के लाइव प्रस्तुत किये गये। इनमें हारमोनियम पर डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, तबले पर संजय भरणे और ऑक्टोपैड पर रवि पात्रो थे। डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने चर्चा में बताया कि गुंजन हाउस में एक आडियो-वीडियो स्टूडियो प्रारंभ करने की योजना है जिससे अंचल के गायक-गायिकाएं और लोक कलाकार लाभान्वित होंगे।

धनोरा में गूंजेगा हर-हर महादेव के उद्घोष, 17 अगस्त को धूमधाम से निकलेगी डांक कांवड़ यात्रा

नई दृष्टिबिंदु / रिसाली-भिलाई

बाबा दरबार पावन धाम धनोरा दुर्ग में बढ़े ही धूमधाम से डांक कांवर यात्रा मनाया जाएगा। दरबार के लक्ष्मण बाबा ने बताया कि सुबह 6 बजे महावीर उद्यान में इकट्ठा होकर महावीर उद्यान से शिवनाथ नदी के लिए रवाना होगे। जहां पर पहुंच कर शिवनाथ नदी से जल लेकर दौड़ते हुए गंज पारा, कचहरी चौक, महाराजा चौक से बोरसी फिर धनोरा में गोल्डन चौक से मुख्य गली बाजार चौक होते हुए महावीर उद्यान पहुंचकर शिवजी में जल चढ़ाकर पूजा पाठ करके अपने-अपने घर को प्रस्थान करेंगे।

दोपहर से रुद्राभिषेक पुजा पाठ विद्वान पंडित द्वारा करके फिर खिचड़ी प्रसाद वितरण किया जाएगा। दोपहर 2 बजें से मानस गान मानस मंडली द्वारा इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल रहे दरबार के लक्ष्मण बाबा नंद पंडा विनोद कुमार साहू, राजेश चन्दाकर, डोरेलाल, दिनेश यादव, रामु यादव, ओमकार साहू, टीकम, गुमान साहू, गुलाब साहू, भोलु, खिलेशवर साहू, सुंदर सपरे, चन्द्र कांत देवांगन, एमलाल देवांगन, कल्याण देवांगन, ललित साहू, रोशन साहू, डॉ. धनेश्वर साहू, राजू देशमुख, बबलू गज्जू, रायपुरीहा, जीवराखन ठेकेदार, बाबू लाल साहू, दिनेश साहू, राजू यादव, मनसुखा साहू, मनोज पटेल, मुनना गंधर्व, सुनील पेटर, वासुदेव स्से, पूर्व उपसरपंच कुंभकरण पटेल, चेतन साहू, तोमन गजपाल, उमेश साहू, हेमंत साहू आदि भक्तगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे यह जानकारी दरबार प्रतिनिधी चन्द्र कांत कोसरे एवं कुंज लाल साहू ने दी है।

बीएसपी में लर्निंग चैंपियंस सम्मानित, संगठनात्मक क्षमता विकास को मिला बढ़ावा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन-ज्ञानार्जन एवं विकास (एचआर-एलएंडडी) विभाग ने संगठन में सीखने और ज्ञान साझाकरण की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान क्षमता विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को लर्निंग चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार ने चयनित अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि निरंतर सीखना, कौशल विकास और ज्ञान का आदान-प्रदान संगठनात्मक उत्कृष्टता की आधारशिला है। बदलते औद्योगिक परिवेश में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम और ज्ञान-संपन्न मानव संसाधन का विकास जरूरी है।

सेल लर्निंग एम्बेसडर: रेणु गुप्ता, कोमल मेहरा, वोन्या मुखर्जी, नीना राठौर, दीप्ति राज, डी. श्वेता, श्रुति मेनन, अनुराधा ध्रुव और दिव्याश्री को संगठन में सीखने की संस्कृति और सहकर्मी-आधारित क्षमता विकास को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया।

75वीं एसएचआरएम संवर्धन एवं तरंग: धीरज सिंह परिहार, आनंद शुक्ला, राम दत्त शर्मा, संदीप झा, विजय कुमार सैनी, अजय नाथ गोपीनाथन पिल्लई, श्रुति मेनन और चेतन अशोक फुटाने को संगठनात्मक अधिगम और आधुनिक एचआर पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस-2026: लर्निंग एम्बेसडर ब्रेक्स: प्रीति भटनागर, अदिति सत्पथी, संविता पंडा, अमृता गंगराड़े, पुष्पा एम्ब्रोस और सुनीता बोरकर को सीखने, ज्ञान साझाकरण और पेशेवर नेतृत्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम महाप्रबंधक प्रभारी (एचआर-एलएंडडी) संजीव कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन और उप प्रबंधक (एचआर-एलएंडडी) सुष्मिता पाटला के समन्वय में आयोजित हुआ।

नवाचारी सुरक्षा उपायों से बीएसपी ने कार्यस्थल सुरक्षा को किया और सुदृढ़

जून में एसएमएस, सीओ एंड सीसीडी, ओएचपी समेत कई विभागों में लागू हुई नई प्रणालियां

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र ने जून 2026 में कार्यस्थल सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए विभिन्न उत्पादन विभागों में कई नवाचारी इंजीनियरिंग, डिजिटल और निवारक सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य परिचालन जोखिमों को कम करना, लाइन ऑफ फायर के खतरों को रोकना और तकनीक आधारित सुरक्षित कार्य वातावरण तैयार करना है।

प्रमुख सुरक्षा सुधार:

सीओ एंड सीसीडी: सेंट्रल ओर हैंडलिंग क्षेत्र के वैगन टिपलर-07 में उन्नत आईएफआर प्रोटेक्शन स्विच लगाया गया। यह स्विच वैगन की स्थिति पर नजर रखते हुए निर्धारित सीमा से आगे बढ़ने पर स्वत: टिपलिंग प्रक्रिया को रोक देता है। इससे उपकरण क्षति और दुर्घटनाओं की संभावना घटी है।

एसएमएस-2: आरएच डीगैसर प्री-हीटिंग सिस्टम में स्पार्क प्लग के स्थान पर पायलट बर्नर आधारित इग्निशन सिस्टम स्थापित किया गया। अब फ्लेम सेंसर से ली की पुष्टि के बाद ही मुख्य कोक ओवन गैस वाल्व संचालित होगा, जिससे विस्फोट की आशंका कम हुई। इसी विभाग में कन्वर्टर के 8 मीटर क्षेत्र में सेमी पोर्टल क्रेन के पास डिमार्केशन लाइन बनाकर लाइन ऑफ फायर पहचान पहल भी शुरू की गई।

एसएमएस-3: फेरो-एलॉय एडिशन सिस्टम के 36 मीटर और 40 मीटर कन्वेयर च्यूट पर च्यूट जैम लिमिट स्विच लगाए गए। च्यूट में अवरोध आने पर सिस्टम स्वत: बेल्ट रोक देगा, जिससे उपकरण सुरक्षित रहेंगे।

एसपी-3: जेड-16 बीसी-1 एवं बीसी-2 बेल्ट कन्वेयर की पूरी लंबाई में निरंतर साइड गार्डिंग लगाई गई, ताकि कर्मियों का संपर्क गतिशील कन्वेयर से न हो।

ओएचपी: सभी स्टैकर-रिक्लेमर पर पोर्टेबल व्हील-लॉकिंग स्किड लगाए गए। तेज हवा या खराब मौसम में यह द्वितीयक एंकरिंग के रूप में काम कर उपकरणों की अनियंत्रित गति रोकेंगे।

इन उपायों से बीएसपी ने परिचालन जोखिम घटाने, उपकरणों की विश्वसनीयता बढ़ाने और सुरक्षित व उत्पादक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

14 सितंबर से सुर, ताल और घुंघरुओं की झंकार से गूंजेगा 41 वें चक्रधर समारोह का मंच

स्थानीय प्रतिभाओं और छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों को मिलेगा मंच, रामलीला मैदान में 10 दिनों तक सजेगा शास्त्रीय संगीत, नृत्य और लोक संस्कृति का महाकुंभ

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रायगढ़ जिले की सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक 41वें चक्रधर समारोह-2026 इस वर्ष 14 से 23 सितंबर 2026 तक स्थानीय रामलीला मैदान में आयोजित होगा। दस दिवसीय इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन को भव्य, सुव्यवस्थित और यादगार बनाने के लिए आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलाकार चयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर एवं चक्रधर समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष मयंक चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कलाकारों के चयन, कार्यक्रम की रूपरेखा तथा आयोजन की प्रशासनिक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि चक्रधर समारोह केवल शास्त्रीय कला का मंच नहीं, बल्कि रायगढ़ और छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस वर्ष आयोजन में स्थानीय कलाकारों, नवोदित प्रतिभाओं तथा छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं लोक संस्कृति को विशेष स्थान दिया जाए, ताकि क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत का प्रभावी प्रदर्शन हो सके।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ-साथ रायगढ़ और प्रदेश के लोक कलाकारों को भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ी लोकगीत, लोकनृत्य, पारंपरिक सांस्कृतिक विधाओं तथा स्थानीय प्रतिभाओं की प्रस्तुति समारोह का विशेष आकर्षण होगी। इससे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिलेगी। समारोह के दौरान शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य, लोक कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का संतुलित कार्यक्रम तैयार करने पर समिति ने विस्तार से विचार-विमर्श किया। विशेषज्ञों ने कार्यक्रमों की समय-सारिणी, प्रस्तुति की गुणवत्ता तथा दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन्हें आयोजन की अंतिम रूपरेखा में शामिल किया जाएगा।

बैठक में मोती महल रायगढ़ (राज परिवार) से देवेन्द्र प्रताप सिंह एवं सुश्री उवर्शी देवी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिजीत बबन पठारे, एडीएम अपूर्व प्रियेश टोप्पो, सहायक कलेक्टर गोकुल आर.के. संयुक्त कलेक्टर श्रीमती पूजा बंसल, प्रो. अम्बिका वर्मा, प्रदेश संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अनुपम पाल, कलाकार भूपेन्द्र बरेठ तथा प्राचार्य राजेश डेनियल सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

आयोजन स्थल पर व्यवस्थाओं को लेकर विभागों को मिले निर्देश

बैठक में रामलीला मैदान में मंच निर्माण, आकर्षक सज्जा, दर्शक दीर्घा, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता तथा अन्य जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभागों को विस्तृत कायर्योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। आयोजन के प्रत्येक पहलू में विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।

सांस्कृतिक गरिमा और भव्यता के साथ होगा आयोजन

बैठक में आयोजन समिति ने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष का 41वां चक्रधर समारोह सांस्कृतिक गरिमा, उत्कृष्ट व्यवस्थाओं और उच्चस्तरीय प्रस्तुतियों के कारण पहले से अधिक भव्य और ऐतिहासिक होगा। राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के साथ स्थानीय एवं छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों की सहभागिता समारोह को नई पहचान देगी तथा रायगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को देशभर में और अधिक प्रतिष्ठा दिलाएगी।

खास खबर

मुख्यमंत्री साय ने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पर्वतारोही अमिता श्रीवास को दी बधाई

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जांजगीर-चांपा जिले की होनहार पर्वतारोही सुश्री अमिता श्रीवास ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इतिहास रचने वाली अमिता श्रीवास को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर विधायक श्रीमती गोमती साय उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अमिता श्रीवास ने अपने साहस, अदम्य इच्छाशक्ति, अनुशासन और अटूट संकल्प के बल पर विश्व की सबसे ऊँची चोटी पर भारत का तिरंगा लहराकर न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उनकी यह उपलब्धि प्रदेश के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद लक्ष्य के प्रति समर्पण और निरंतर प्रयास से असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अमिता श्रीवास की सफलता प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का सशक्त उदाहरण है।

उल्लेखनीय है कि जांजगीर-चांपा जिले की रहने वाली पवर्तारोही अमिता श्रीवास ने 22 मई को समुद्र तल से 8,848.86 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाया है।

कुकराचुंदा-मोहभटठा और बोड़तरा रेलवे फाटक 19 जुलाई तक बंद रहेगा

रायपुर। रायपुर रेल मंडल में रेलवे भाटापारा-हथबंद स्टेशनों के मध्य समपार क्रमांक 386 (कि.मी. 768/14 - 16) डाउन लाइन स्थित ट्रेक में आवश्यक मरम्मत कार्य के लिए 18 जुलाई 2026 सुबह 8 बजे से 19 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे तक सड़क यातायात का आवागमन बंद रहेगा ल कुकराचुंदा - मोहभटठा रोड रेलवे समपार क्र.389 गेट को स्थाई रूप से बंद करने के संबंध में रायपुर रेल मंडल में रेलवे भाटापारा-हथबंद स्टेशनों के मध्य समपार क्रमांक 389 (कि.मी. 774/14A - 16A) डाउन लाइन स्थित ट्रेक में आवश्यक मरम्मत कार्य के लिए 18 जुलाई 2026 सुबह 8 बजे से 19 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे तक सड़क यातायात का आवागमन बंद रहेगा।

ग्रामीण विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना विकसित छग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : मुख्यमंत्री

सीएम साय और विस अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भावना दीदी की साइंस पाठशाला को दिखाई हरी झंडी

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने और विज्ञान आधारित शिक्षा को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा परिसर से भावना दीदी की साइंस पाठशाला के अंतर्गत संचालित निःशुल्क मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अत्याधुनिक मोबाइल लैब पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों तक पहुँचकर विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, ड्रोन, 3डी प्रिंटिंग, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), एयरोमॉडलिंग तथा ऑगमेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी (AR/VR) जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा साइंस और डिजिटल तकनीकों की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को भी इन उभरती हुई तकनीकों का ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि अवसरों में किसी प्रकार की असमानता न रहे और गाँव का बच्चा भी भविष्य की तकनीकों में उतना ही सक्षम बने जितना किसी महानगर का विद्यार्थी होता है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य भी विद्यार्थियों में कौशल, नवाचार, प्रयोगधर्मिता और रचनात्मक सोच का विकास करना है। यह मोबाइल लैब उसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है, जो बच्चों को केवल तकनीक का उपयोग करना ही नहीं सिखाएगी, बल्कि उन्हें नई तकनीकों के निर्माण और नवाचार की दिशा में भी प्रेरित करेगी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है तथा बच्चों को समय के साथ नई तकनीकों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भावना दीदी की साइंस पाठशाला जैसी अभिनव पहल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी वही अवसर उपलब्ध कराएगी, जो बड़े शहरों के विद्यार्थियों को मिलते हैं। इससे बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी, नवाचार की सोच विकसित होगी और वे आधुनिक तकनीकों को समझने के साथ उनका व्यावहारिक उपयोग भी सीख सकेंगे।

उन्होंने पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा की सराहना करते हुए कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, नवाचार और युवा प्रतिभाओं के विकास के लिए निरंतर नए प्रयास कर रही हैं। यह मोबाइल साइंस लैब भी उनकी दूरदर्शी सोच और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है, जो आने वाले समय में हजारों विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।

मोबाइल लैब की तकनीकी सुविधाओं का किया अवलोकन : कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब का अवलोकन किया। प्रशिक्षकों ने उन्हें लैब में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों, प्रशिक्षण मॉड्यूल और शिक्षण प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने विशेष रुचि लेते हुए एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन और अन्य तकनीकी उपकरणों का स्वयं निरीक्षण किया तथा यह जाना कि विद्यार्थी किस प्रकार इन तकनीकों को व्यवहारिक रूप से सीखेंगे। उन्होंने इसे ग्रामीण प्रतिभाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने वाला अभिनव और प्रेरणादायी प्रयास बताया। उन्होंने लैब में प्रदर्शित विभिन्न तकनीकी मॉड्यूल का अवलोकन करते हुए प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्रक्रिया की जानकारी ली और बच्चों को मिलने वाले व्यावहारिक अनुभव की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रयोग आधारित शिक्षा विद्यार्थियों में सीखने की रुचि और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाती है।

एक वर्ष में पाँच हजार से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचेगी तकनीकी शिक्षा : उल्लेखनीय है कि यह मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों तथा सरस्वती शिशु मंदिरों में जाकर प्रशिक्षण प्रदान करेगी। पाँच अनुभवी प्रशिक्षकों की टीम प्रत्येक विद्यालय में तीन से पाँच दिनों की कायर्शाला आयोजित करेगी, जिसमें विद्यार्थियों को अक, रोबोटिक्स, ड्रोन एवं एयरोमॉडलिंग, 3डी प्रिंटिंग, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा AR/VR जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

"महादेव सट्टा एप भाजपा का सट्टा प्रकोष्ठ" : भूपेश बघेल का हमला

विकास गर्ग की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

केंद्र से 4 सवाल

बघेल ने केंद्र की भाजपा सरकार से 4 सवाल पूछे:

1. महादेव सट्टा एप पर भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? यह एप अब तक कैसे चल रहा है?
2. नवनीत सहगल और हिरेन जोशी की जांच अभी तक क्यों नहीं हुई?
3. ईडी इन अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंची?
4. विदेशों में बैठे एप के ऑपरेटरों को सरकार वापस क्यों नहीं ला पाई?

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

महादेव सट्टा एप मामले में ईडी द्वारा विकास गर्ग की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर आरोप लगाया कि महादेव सट्टा एप भाजपा के संरक्षण में चलाया जा रहा "सट्टा प्रकोष्ठ" है।

श्री बघेल ने लिखा कि विकास गर्ग भाजपा दिल्ली के आर्थिक प्रकोष्ठ का चेयरमैन और पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग का पुत्र है। ईडी ने उसे 1200 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन के मामले में गिरफ्तार किया है और उसकी 900 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास गर्ग महादेव सट्टा एप से हर महीने करीब 450 करोड़ रुपये कमाता था। लेनदेन को लेकर सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर विवाद हुआ जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई की।

गौरतलब है कि ईडी ने हाल ही में महादेव सट्टा एप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विकास गर्ग को गिरफ्तार किया था। भाजपा की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई।

कांग्रेस की कार्रवाई का हवाला

भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ में महादेव एप के खिलाफ पहली कार्रवाई की थी। इस दौरान 72 से अधिक FIR दर्ज हुईं, 400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, हजारों बैंक खाते सीज किए गए और सैकड़ों गैजेट्स, लैपटॉप जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गूगल को एप हटाने और गृह मंत्रालय को लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए भी पत्र लिखा था। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की कार्रवाई से भाजपा तिलमिला गई और उल्टा कांग्रेस पर ही आरोप लगाए।

छग विधानसभा उत्कृष्ट कार्य संस्कृति और स्वस्थ संसदीय परंपरा का एक जीवंत उदाहरण है : राज्यपाल रमेन डेका

प्रदेश के विकास और जनहित के संकल्पों को साकार करने का सशक्त मंच है विधानसभा - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
छत्तीसगढ़ विधानसभा ने स्थापित की उत्कृष्ट संसदीय परंपराएं, लोकतांत्रिक मूल्यों को किया सशक्त - विस अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपने गठन के बाद से लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय गरिमा और अनुशासन की ऐसी उत्कृष्ट परंपराएं विकसित की हैं, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना होती है। यह प्रसन्नता का विषय है कि 1 नवंबर 2025 को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण किया गया था और आज उसी परिसर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण राज्यपाल रमेन डेका के करकमलों से संपन्न हुआ है। यह विधानसभा की संस्थागत क्षमता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित प्रेक्षागृह में आज उत्कृष्टता अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

लोकतांत्रिक परंपराओं, संसदीय मूल्यों और उत्कृष्ट जनप्रतिनिधित्व को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित इस गरिमामयी समारोह में राज्यपाल रमेन डेका ने विधानसभा परिसर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट संसदीय कार्य के लिए बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक तथा अकलतरा विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक अलंकरण से सम्मानित किया गया। पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए दैनिक पत्रिका के संवाददाता संतराम साहू को उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार अलंकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए आईबीसी-24 के सौरभ सिंह परिहार एवं डॉ. राजेश राज को उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर अलंकरण प्रदान किया गया।

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा लोकसेवा का वह केन्द्र है जहां जनसेवक संसदीय सदन में लोक कल्याण का पावन अनुष्ठान संपादित करते हैं और इसलिए लोकतंत्र में संसदीय सदन को मंदिर की संज्ञा दी गयी है और इस मंदिर की प्रतिष्ठा सभी सदस्यों के आचरण व्यवहार और विचार पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की गणना देश की श्रेष्ठ विधानसभाओं के उदाहरण के रूप में होती है। इस विधानसभा में पक्ष-प्रतिपक्ष के मध्य जो समन्वय है, सामन्जस्य है, और समादर का भाव है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय और अनुकरणीय है।

श्री डेका ने अपने संबोधन में सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकारों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस मंदिर में जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए समर्पण भाव से कार्य करें। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि सभी प्रतिनिधि मिलकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य करें, तभी राज्य निरंतर प्रगति करेगा। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से संवाद, स्वच्छता अभियान में सहभागिता तथा समाज के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले कार्यों को प्राथमिकता देने का भी आह्वान किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा देश की पहली और एकमात्र ऐसी विधानसभा है, जहां गभर्गृह में किसी विधायक के प्रवेश करते ही वे स्वतः निलंबित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि आत्मानुशासन, संसदीय मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। ऐसी विशिष्ट संसदीय परंपराओं ने छत्तीसगढ़ विधानसभा को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई है।

श्री साय ने लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को जनता से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही, जनहित के मुद्दों और लोकतांत्रिक विमर्श को निष्पक्ष एवं तथ्यपरक ढंग से जनता तक पहुँचाने में संसदीय पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सम्मानित पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सम्मानित विधायकों की सराहना करते हुए कहा कि श्री धरमलाल कौशिक का सार्वजनिक जीवन अत्यंत समृद्ध और अनुभवपूर्ण रहा है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए संसदीय परंपराओं को समृद्ध किया है। वहीं राघवेंद्र कुमार सिंह ने प्रथम बार विधायक निर्वाचित होने के बावजूद सदन में तथ्यपूर्ण, अध्ययनशील एवं प्रभावी ढंग से अपनी बात रखकर एक सकारात्मक पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि दोनों जनप्रतिनिधियों का सम्मान लोकतांत्रिक मूल्यों और उत्कृष्ट संसदीय आचरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण के बाद आज नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण विधानसभा के विकास की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की षष्ठम विधानसभा अपने कार्यकाल में उत्कृष्ट संसदीय परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सदैव स्मरणीय रहेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पक्ष और प्रतिपक्ष राजनीतिक मतभेदों के बावजूद प्रदेशहित के विषयों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा करते हैं। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि उत्कृष्टता अलंकरण केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का सम्मान नहीं है, बल्कि यह संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम परंपराओं को प्रोत्साहित करने का माध्यम भी है। ऐसे सम्मान जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक उत्तरदायी तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रेरित करते हैं।

समारोह के सांस्कृतिक आयोजन में देश के प्रख्यात भजन गायक अनूप जलोटा ने अपने लोकप्रिय भजनों की मनोहारी प्रस्तुति देकर उपस्थित जनसमूह को भक्तिरस में सराबोर कर दिया। उनकी मधुर एवं भावपूर्ण प्रस्तुति ने पूरे प्रेक्षागृह को आध्यात्मिक वातावरण से अनुप्राणित कर दिया और कार्यक्रम को अविस्मरणीय बना दिया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, विधायकगण, विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार तथा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़ में PMIS योजना अंतर्गत कल एकदिवसीय पंजीयन शिविर का आयोजन

रायपुर-खैरागढ़। शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़ में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों का पंजीयन कराने के लिए 17 जुलाई 2026 को एकदिवसीय पंजीयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 18 से 25 आयु वर्ग के 10वी/12वीं/ ITI/ डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा जो किसी नियमित जॉब मे नही है, तथा जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से कम है, इस योजना के लिए पात्र हैं। इस शिविर में पात्र एवम इच्छुक अभ्यर्थियों को PMIS 3.0 योजना की जानकारी प्रदान की जाएगी तथा उनका ऑनलाइन पंजीयन निःशुल्क किया जाएगा। सभी इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन पश्चात चयनित अभ्यर्थियों को देश एवं राज्य के टॉप कंपनियों में 6 से 9 माह का इंटर्नशिप प्रदान किया जाता है तथा इंटर्नशिप के दौरान प्रतिमाह 9000 की वित्तीय सहायता तथा आकस्मिक खर्चों के लिए 6,000 का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है। साथ ही इंटर्न स्वतः ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कवर होते हैं, जिसका प्रीमियम सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (आधार से लिंक), ईमेल आईडी, बैक पासबुक, शैक्षणिक अंकसूची एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज सहित प्रातः 11 बजे से अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़ से संपर्क कर सकते हैं।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला क्रमांक : 202607101000020

विषयः- अ-6 अ
मामले की श्रेणीः- राजस्व
सन्ः- 2025-2026
बासीन प.ह.न. 00011 [(हे.)]
पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार नन्द कुमार यादव,
अनावेदक पक्षकार -

-:: ईश्तहार ::-

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक : नन्द कुमार यादव पिता/पति/विभाग-पंछा राम यादव पता-भिलाई द्वारा ग्राम - बासीन प.ह.न. 11 रा.नि.म. जेवरा सिरसा, तहसील व जिला दुर्ग की भूमि ख.न. 692/1 रकबा 0.038 हे. आवेदक के नाम पर दर्ज है ! किन्तु उक्त भूमि वर्तमान पटवारी अभिलेख में आवेदक के नंदकुमार के स्थान पर चुम्मन लाल प्रदर्शित हो रहा है ! जिसे त्रुटी सुधार किये जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है

उपरोक्त भूमि का नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 20/072026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा !

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 04/07/2026 को जारी किया जाता है।

DIKESHWAR SAHU
अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग

-:: ईश्तहार ::-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय का रा.प्र.क्रं. /अ-6/वर्ष 2025-26 में आवेदिका/आवेदक हेमंत कुंभारे आ./ध.प. सुकदेव कुंभारे निवासी - वैशाली नगर सुपेला भिलाई तह. दुर्ग व जिला दुर्ग द्वारा ग्राम कोहका प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. कोहका व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं. 8430/7 रकबा 0.0100 हे. है। जो भूमिस्वामी सुकदेव कुंभारे पिता यादव राम कुंभारे के नाम पर दर्ज है। जिसमें भूमिस्वामी सुकदेव कुंभारे की मृत्यु दिनांक 23/12/2020 को फौत हो जाने के कारण मृतक का नाम खाते से विलोपित कर उसके वैध वारिसानो का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त भूमि फौती नामांतरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 16/07/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/06/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

संपादकीय

सरकार को अफवाह फैलाने का मौका नहीं देना चाहिए

सरकार कुछ देशहित,जनहित में करना चाहती है तो देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं वह खुल कर तो सरकार का विरोध करने सामने नहीं आते हैं लेकिन पर्दे के पीछे से कई तरह के माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए यह अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं कि सरका जो कुछ करने जा रही है वह देशहित व जनहित में नहीं है। इससे तो लोगों को नुकसान होगा। इस बार भी सरकार ने जैसे ही ई-20 ईंधन यानी 20 प्रतिशत एथेनाल मिश्रित पेट्रोल बेचने का फैसला किया वैसे ही देश में अफवाह फैलाने वाले सक्रिय हो गए कि इससे तो गाड़ी खराब हो रही है, गाडी के इंजन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है,गाड़ी का माइलेज कम हो गया है ।सरकार की तरफ से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी व हरदीप सिंह पुरी की तरह से जो कहा गया उससे देश के लोगों को सच्चाई का पता नहीं चला,उल्टे और भ्रम फैल गया।

नितिन गड़करी ने ई-20 के आलोचकों को चुनौती देते हुए कहा कि वह किसी एक कार का नाम बताएं,जिसमें ई-20 का उपयोग करने के कारण कोई समस्या आई हो। उनका कहना था कि देश में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। उनका कहना था कि ई-20 के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही है। पैसा देकर अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने देश भर में उठ रहे सभी सवालों का खारिज करते हुए कहा कि ई-20 से उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। पुरी ने कहा कि वाहन निर्माता कंपनियां और वाहन सर्विस सेंटर दोनो मानते हैं कि ई-20 के इस्तेमाल में कोई दिक्कत नहीं है ।कुछ दिन बाद केंद्र सरकार की तरफ से यह साफ करने पर कि ई-20 ईंधन के प्रयोग से वाहन का माइलेज तीन से पांच प्रतिशत तक कम हो सकता है। यह तो साफ हो जाता है कि ई-20 के मामले में सरकार ने सच्चाई को सामने लाने में देरी की और देश में कुछ लोगों को अफवाह फैलाने का मौका मिला है तो इसके लिए मंत्री व केंद्र सरकार भी दोषी हैं।

जब सरकार के किसी कदम से देश में गलत बाते फैलाई जाती है, अफवाह फैलाई जाती हैं तो सच जनता को बताना सरकार का काम होता है। सरकार को सच बताने में देरी के कारण देश में अफवाह फैलती है और सरकार के देशहित व जनहित मे उठाए जा रहे कदम का विरोध शुरू हो जाता है कि सरकार गलत कर रही है। सरकार बाद मे बता रही है कि वाहन का माइलेज तीन से पांच प्रतिशत कम हो सकता है,सरकार बाद मे बता रही है कि सरकार शुध्द पेट्रोल या ई-20 पर लौटने वाली नही है ।सरकार बाद में बता रही है कि पिछले कई सालों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको ने एथेनाल व संबंधित बुनियादी ढांचे में लगभग एक लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निवेश किया है। इसके तहत एथेनाल संयंत्र,डिस्टलरी,भंडारण सुविधाएं, लाजिस्टिक नेटवर्क बनाए गए हैं। यह सब सरकार पहले बता सकती थी इससे सरकार की आलोचना नहीं होती और लोगों को झूठ फैलाने का मौका नहीं मिलता।

सरकार अब बता रही है कि ई-20 क्यों जरूरी है। सरकार पहले भी बता सकती थी कि विदेशी तेल पर निर्भरता घटाने,किसानों की आय बढ़ाने व देश में प्रदूषण कम करने के लिए ई-20 का उपयोग जरूरी है। यह सच है कि इससे कुछ नुकसान हैं लेकिन फायदे उससे बड़े हैं। यह सच है कि इससे देश को फायदा है लेकिन लोगों को नुकसान भी तो होगा। लोगों का कहना है कि माइलेज घटने से, वाहन का मेंटेंनेंस खर्च बढ़ने से उनका वाहन का खर्च बढ़ता है। यानी ऊर्जा सुरक्षा,पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आय तीन लक्ष्यों को सरकार ने एक साथ साधने का काम किया है, इससे देश को फायदा होगा लेकिन वाहन मालिको तो नुकसान होगा। उनके फायदे के विषय में सरकार ने सोचा नहीं है। सरकार को उनके फायदे के बारे में सोचना चाहिए। सीधी सी बात है कि ई-20 का उपयोग करने से वाहन का माइलेज कम होता है तो ईंधन पहले से ज्यादा लगेगा यानी ईंधन का खर्च के साथ ही वाहन के रखरखाव का खर्च भी तो बढता है।

कुछ लोगों का कहना है कि ई-20 सामान्य पेट्रोल से सस्ता मिलता तो भी वाहन मालिकों के लिए फायदे की बात होती। ई-20 तो सामान्य पेट्रोल में महंगा है, कई बार जब अंतराष्ट्रीय बाजार मे कच्चा तेल सस्ता होता है तो तब एथेनाल की लागत पेट्रोल से और ज्यादा हो जाएगी। यानी ई-20 कोई सस्ता ईंधन तो नही है। ई-20 एक राष्ट्रीय नीति है,देश के फायदे के लिए है तो इसका नुकसान वाहन मालिकों को अकेले क्यो उठाना चाहिए ।सरकार कर संरचना,मूल्य निर्धारण व अन्य प्रोत्साहनों के जरिए इस नुकसान को कम कर सकती है। सरकार जनता को सच बताएगी तो जनता उसे स्वीकार करेगी और सरकार का सहयोग भी करेगी। इसके लिए जरूरी है कि सरकार कोई भी फैसला करती है तो वह सच जनता के सामने रखे ।कोई भी बड़ा सुधार तब ही सफल होता है जब उसका उद्देश्य अच्छा हो और उसे जनता की स्वीकृति प्राप्त हो। देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है तो यह अच्छी बात है। इसकी सफलता के लिए जनता का विश्वास भी जरूरी है ।जनता के सहयोग बिना कोई सुधार सफल नहीं होता है इसलिए सरकार को जनता का सहयोग पहले प्राप्त करना चाहिए ।उसका भरोसा पहले जीतना चाहिए।

आस्था, परम्परा, आध्यात्मिक चेतना का विराट उत्सव

ललित गर्ग

आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से प्रारम्भ होकर दस दिनों तक चलने वाली भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, लोकआस्था, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक दर्शन का विराट उत्सव है। पुरी की यह महायात्रा हजारों वर्षों की परम्परा का जीवंत प्रतीक है, जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। इसी कारण इसे ह्यमहायात्राह्न कहा जाता है। भारत के चार धामों में प्रतिष्ठित श्री जगन्नाथ धाम की यह यात्रा देश ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व के करोड़ों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र बनती है। वर्ष 2026 की रथयात्रा भी अपार श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई जा रही है, किन्तु इस बार इसके साथ एक नया विवाद भी जुड़ गया है। देश एवं विदेश के अनेक स्थानों पर इस्कॉन द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग तिथियों पर रथयात्राएं आयोजित किए जाने पर कुछ धार्मिक एवं परम्परावादी संगठनों ने आपत्ति व्यक्त की है। उनका मत है कि जगन्नाथ रथयात्रा की तिथि वही होनी चाहिए जो पुरी श्रीमंदिर द्वारा निर्धारित होती है। दूसरी ओर इस्कॉन का तर्क है कि विदेशों में स्थानीय प्रशासन की अनुमति, सार्वजनिक अवकाश, मौसम तथा अन्य व्यावहारिक कारणों से कभी-कभी तिथि में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। यह विवाद केवल तिथि का नहीं, बल्कि परम्परा और वैश्विक विस्तार के बीच संतुलन खोजने का विषय बन गया है।

वास्तव में यह समझना आवश्यक है कि पुरी की रथयात्रा और अन्य स्थानों पर आयोजित रथयात्राओं का स्वरूप अलग-अलग हो सकता है, किन्तु उनका मूल उद्देश्य भगवान जगन्नाथ की भक्ति, लोककल्याण और धर्मप्रचार ही है। यदि परम्परा का सम्मान बना रहे और श्रद्धा अक्षुण्ण रहे तो मतभेद संवाद के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। धर्म का मूल स्वरूप जोड़ना है, विभाजन करना नहीं। पुरी का श्रीमंदिर भगवान जगन्नाथ का मुख्य धाम है। लगभग 800 वर्ष पुराने इस मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण जगन्नाथ स्वरूप में अपने बड़े भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। प्रतिवर्ष केवल एक बार तीनों देव विग्रह अपने गभर्गृह से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है। सामान्य दिनों में जहां भगवान के दर्शन सीमित होते हैं, वहीं रथयात्रा में प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के भगवान के साक्षात दर्शन कर सकता है।

यात्रा की तैयारियां अक्षय तृतीया से प्रारम्भ हो जाती हैं। उसी दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के तीनों विशाल रथों का निर्माण आरम्भ होता है। प्रत्येक वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। यद्यपि उनका स्वरूप और आकार सदियों से समान रहता है, फिर भी प्रत्येक वर्ष नई लकड़ी, नई सज्जा और नवीन निर्माण किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ गरुड़ध्वज (कपिलध्वज), बलभद्र का तालध्वज तथा सुभद्रा का दर्पदलन अथवा पद्मध्वज कहलाता है। इन रथों के निर्माण की प्रक्रिया केवल शिल्पकला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना मानी जाती है। कारीगर विशेष धार्मिक नियमों का पालन करते हुए इन्हें बनाते हैं। यह परम्परा हमें यह संदेश देती है कि प्रत्येक वर्ष मनुष्य भी अपने भीतर की ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और लोभ को त्यागकर स्वयं का नव-निर्माण करे।

रथयात्रा के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। कहा जाता है कि एक बार सुभद्रा ने द्वारका नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्रीकृष्ण और बलराम ने उन्हें अलग रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया। उसी स्मृति में तीनों भाई-बहनों की संयुक्त रथयात्रा निकाली जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान की अपूर्ण प्रतिमाओं का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था, जो आज भी जगन्नाथ संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इस महायात्रा का एक अत्यन्त मार्मिक पक्ष यह भी है कि स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान अस्वस्थ माने जाते हैं और लगभग पन्द्रह दिनों तक सार्वजनिक दर्शन नहीं देते। इसके पश्चात वे रथों पर आरूढ़ होकर अपनी मौसी के घर गुण्डिचा मंदिर जाते हैं। वहां नौ दिनों तक विश्राम करते हैं और फिर बहुड़ा यात्रा के माध्यम से पुनः श्रीमंदिर लौटते हैं। लौटते समय भगवान का पोडा पीठा ग्रहण करना, पंचमी को देवी लक्ष्मी का रुष्ट होकर रथ का पहिया तोड़ना तथा बाद में भगवान द्वारा उन्हें मनाने की परम्परा भक्तिभाव एवं मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है।

पुरी की रथयात्रा का एक अन्य अद्भुत दृश्य छेरा पहरा है। गजपति महाराज स्वयं स्वर्ण निर्मित झाड़ू से रथों के मार्ग की सफाई करते हैं। यह परम्परा संदेश देती है कि ईश्वर के समक्ष राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं। सत्ता का सवोच्च पद भी सेवा से बड़ा नहीं हो सकता। रथयात्रा के समय जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद भी विशेष आकर्षण का केन्द्र होता है। विश्व की सबसे बड़ी मंदिर रसोइयों में से एक इस रसोई में मिट्टी के पात्रों में प्रसाद बनाया जाता है। दाल, चावल, सब्जियाँ, मालपुआ, गजामूंग, लाई, नारियल तथा अनेक प्रकार के व्यंजन अत्यंत अल्प मूल्य पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि समानता और साझेदारी का प्रतीक है।

धार्मिक ग्रन्थों में रथयात्रा का अत्यन्त महत्व बताया गया है। स्कन्द पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण तथा उत्कल खण्ड में भगवान जगन्नाथ की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। मान्यता है कि रथयात्रा के दर्शन एवं रथ को स्पर्श करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं तथा रथ खींचने वाले को मोक्ष का अधिकारी माना गया है। यद्यपि इन मान्यताओं का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन-रथ को धर्म, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलाता है, वही वास्तविक मुक्ति प्राप्त करता है। जगन्नाथ रथयात्रा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सामाजिक समरसता है। इस अवसर पर जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र अथवा सम्प्रदाय का कोई भेद नहीं रहता। लाखों श्रद्धालु एक साथ रथ की रस्सी खींचते हैं। यही वह क्षण होता है जब धर्म केवल पूजा-पद्धति न रहकर सामाजिक एकता का उत्सव बन जाता है।

आज यह यात्रा केवल पुरी तक सीमित नहीं रही। भारत के लगभग सभी प्रमुख नगरों सहित अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और अनेक यूरोपीय देशों में भी जगन्नाथ रथयात्रा आयोजित होती है। विशेष रूप से इस्कॉन ने इस परम्परा को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। करोड़ों विदेशी भक्तों ने इसी माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण एवं जगन्नाथ संस्कृति को जाना है। इसलिए यदि कहीं तिथियों को लेकर व्यावहारिक परिवर्तन भी किए जाएँ तो उनके पीछे धार्मिक अवमानना नहीं, बल्कि स्थानीय व्यवस्थाओं की विवशता भी हो सकती है। फिर भी यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि जहाँ तक सम्भव हो, श्रीमंदिर की परम्परा और निर्धारित तिथि का सम्मान किया जाए, ताकि सम्पूर्ण विश्व में एकात्मता का संदेश और अधिक सुदृढ़ हो।

दार्शनिक दृष्टि से रथ मनुष्य के शरीर का, भगवान आत्मा का तथा रथ को खींचने वाली रस्सियाँ समाज और लोकशक्ति का प्रतीक हैं। आत्मा तभी सार्थक होती है जब समाज सहयोग करे और समाज तभी श्रेष्ठ बनता है जब उसके केन्द्र में ईश्वर, नैतिकता और आत्मशुद्धि का भाव हो। यही कारण है कि जगन्नाथ रथयात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मविशुद्धि, लोकमंगल, समरसता, सेवा और आध्यात्मिक जागरण का अनुपम पर्व है। वतर्मान समय में जब समाज अनेक प्रकार के वैचारिक, सामाजिक और धार्मिक विभाजनों से गुजर रहा है, तब भगवान जगन्नाथ की यह महायात्रा हमें स्मरण कराती है कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य विवाद नहीं, बल्कि संवाद है। वर्चस्व नहीं, बल्कि समन्वय है और बाहरी आडम्बर नहीं, बल्कि अंतःकरण की पवित्रता है। यही इस महायात्रा का सनातन संदेश है कि जीवन का रथ तभी सही दिशा में चलता है जब उसमें श्रद्धा, सेवा, समरसता, आत्मसंयम और लोककल्याण के पहिए समान गति से चलते रहें। यही जगन्नाथ महायात्रा की शाश्वत महिमा है और यही इसकी वैश्विक प्रासंगिकता।

शाह-योगी की दिल्ली बैठक से बदल गई यूपी चुनाव की सियासी बिसात

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनका आधिकारिक एजेंडा भले सार्वजनिक न किया जाए, लेकिन उनके राजनीतिक संदेश लंबे समय तक महसूस किए जाते हैं। मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच करीब 40 मिनट चली बैठक भी ऐसी ही एक मुलाकात मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कीं, लेकिन जिस समय यह बैठक हुई और उसके पहले तथा बाद की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर डालें तो तस्वीर कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती है।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ट्रस्ट और सरकार को नोटिस, भाजपा के संगठनात्मक फेरबदल, 2027 विधानसभा चुनाव की शुरुआती तैयारी और विपक्ष के बदलते सामाजिक समीकरण इन सभी घटनाओं के बीच हुई यह बैठक राजनीतिक गलियारों में कई सवाल छोड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की धुरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने देशभर में 240 सीटें जीतीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टी का आंकड़ा 62 से घटकर 33 पर आ गया। सहयोगियों के साथ एनडीए की संख्या 36 रही, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का रिकॉर्ड बनाया और कांग्रेस ने भी छह सीटें अपने खाते में जोड़ लीं। सबसे बड़ा राजनीतिक झटका अयोध्या वाली फैजाबाद लोकसभा सीट पर लगा, जहां राम मंदिर निर्माण के बावजूद भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से पार्टी लगातार उन कारणों की समीक्षा कर रही है जिनकी वजह से अपेक्षित राजनीतिक लाभ नहीं मिल सका।

इसी पृष्ठभूमि में भाजपा का पूरा फोकस अब 2027 विधानसभा चुनाव पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 202 सीटों का बहुमत चाहिए। 2022 में भाजपा गठबंधन ने 273 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन 125 सीटों तक पहुंचा था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण बदलते दिखे हैं। भाजपा यह मानकर चल रही है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा से अलग होते हैं, फिर भी पार्टी किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। दिल्ली में शाह और योगी की मुलाकात को इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बैठक में सिर्फ कानून-व्यवस्था या विकास परियोजनाओं की समीक्षा नहीं हुई होगी, बल्कि संगठन, सामाजिक समीकरण, विपक्ष की रणनीति और चुनावी नैरेटिव पर भी विस्तार से चर्चा हुई होगी। खासतौर पर ऐसे समय में जब विपक्ष लगातार अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गड़बड़ी के मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी होने के बाद भाजपा भी अतिरिक्त सतर्क नजर आ रही है क्योंकि पार्टी नहीं चाहती कि विपक्ष धार्मिक आस्था से जुड़े इस विषय को उसके खिलाफ राजनीतिक अभियान में बदल दे।

दिलचस्प बात यह है कि शाह-योगी मुलाकात से कुछ दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश दौरा भी इसी रणनीतिक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्रियों, प्रदेश संगठन, सांसदों, विधायकों और जिला स्तर तक के पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इन बैठकों में सबसे अधिक जोर संगठनात्मक अनुशासन, बूथ प्रबंधन और लोकसभा चुनाव में सामने आई कमजोरियों को दूर करने पर दिया गया। पार्टी नेतृत्व ने साफ संदेश दिया कि व्यक्तिगत बयानबाजी या गुटबाजी से बचते हुए सभी नेताओं को एक ही राजनीतिक लाइन पर काम करना होगा। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब सामाजिक समीकरणों की है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले के सहारे उल्लेखनीय सफलता हासिल की। अब अखिलेश यादव इस दायरे को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ समेत कई जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि समाजवादी पार्टी गैर-यादव पिछड़ों के साथ ब्राह्मण मतदाताओं के एक हिस्से को भी जोड़ने में सफल होती है तो मुकाबला और कठिन हो सकता है।

इसी वजह से भाजपा भी समानांतर सामाजिक रणनीति पर काम कर रही है। गैर-यादव ओबीसी, गैर-जाटव दलित, महिला मतदाता, लाभार्थी वर्ग और युवा वोटरों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के करोड़ों लाभार्थियों को भाजपा अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की संख्या भी दो करोड़ से अधिक बताई जाती है। पार्टी का मानना है कि इन्हीं लाभार्थियों के बीच दोबारा मजबूत पकड़ बनाना चुनावी जीत की कुंजी होगी। दूसरी ओर विपक्ष पूरी ताकत से भाजपा के खिलाफ नया नैरेटिव तैयार करने में जुटा है। अयोध्या चढ़ावा विवाद, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और स्थानीय असंतोष जैसे मुद्दों को लगातार उठाया जा रहा है। हाल के दिनों में लखनऊ, मथुरा और अन्य शहरों में लगे राजनीतिक पोस्टरों ने भी माहौल को और गर्म कर दिया है। एक ओर भाजपा समर्थक खेमे की तरफ से समाजवादी पार्टी पर तीखे राजनीतिक हमले किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर सपा इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। यानी 2027 की लड़ाई सिर्फ विकास बनाम विकास नहीं होगी बल्कि नैरेटिव, प्रतीक और भावनात्मक मुद्दों की भी होगी। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास परियोजनाओं की गति तेज करने में जुटे हैं। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, डिफेंस कॉरिडोर, एयरपोर्ट, मेट्रो और औद्योगिक निवेश परियोजनाओं पर तेजी से काम कराया जा रहा है। फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लगभग 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलने का दावा किया गया था। सरकार का कहना है कि इनमें से बड़ी संख्या में परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। चुनाव से पहले इन परियोजनाओं का असर दिखाना भाजपा की प्राथमिकता होगी। राजनीतिक संकेत इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल पर विशेष जोर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान कई सीटों पर स्थानीय स्तर पर संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय की कमी की चर्चा हुई थी। अब भाजपा इस गलती को दोहराना नहीं चाहती। बूथ समितियों के पुनर्गठन से लेकर शक्ति केंद्रों को सक्रिय करने तक व्यापक अभियान की तैयारी चल रही है। पार्टी का लक्ष्य 2027 से पहले हर बूथ पर सक्रिय संगठन खड़ा करना है। दिल्ली में हुई शाह-योगी मुलाकात का सबसे बड़ा संदेश यही माना जा रहा है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी को लेकर अब प्रतीक्षा की स्थिति में नहीं है।

सिंधु जल संधि : आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और बदलती कूटनीति

राजेश जैन

भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हुई सिंधु जल संधि को लंबे समय तक दुनिया के सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय जल समझौतों में गिना जाता रहा। यह संधि तीन युद्धों, कारगिल संघर्ष, संसद हमले, मुंबई हमले और दोनों देशों के बीच लगातार तनाव के बावजूद छह दशक तक कायम रही। लेकिन अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पहली बार इस संधि को स्थगित करने का फैसला लेकर स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद और सामान्य द्विपक्षीय संबंध अब साथ-साथ नहीं चल सकते। ऐसे में यह विवाद अब केवल पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय कानून, जल संसाधन और दक्षिण एशिया की भविष्य की राजनीति जैसे कई आयाम जुड़ चुके हैं। हाल में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विदेश मंत्री इसहाक डार और पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी की तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद सिंधु जल संधि एक बार फिर चर्चा में है।

जानिए, क्या है सिंधु जल संधि

सिंधु नदी प्रणाली में छह प्रमुख नदियां शामिल हैं- सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन नदियों का जलग्रहण क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान तक फैला है तथा करोड़ों लोगों की आजीविका इन्हीं पर निर्भर करती है।

1947 के विभाजन के बाद पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया। 1948 में भारत द्वारा कुछ नहरों का पानी अस्थायी रूप से रोके जाने के बाद स्थिति गंभीर हुई। इसके समाधान के लिए विश्व बैंक ने मध्यस्थता की और करीब नौ वर्षों की लंबी बातचीत के बाद 1960 में कराची में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत रावी, ब्यास और सतलुज का उपयोग भारत को मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश जल उपयोग पाकिस्तान के हिस्से में गया। कुल जल प्रवाह का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान और लगभग 20 प्रतिशत भारत को मिला। यही वजह है कि भारत में समय-समय पर यह सवाल उठता रहा कि ऊपरी धारा वाला देश होने के बावजूद उसने अपेक्षाकृत अधिक उदारता क्यों दिखाई।

भारत ने क्या दिया और क्या पाया

सामान्य धारणा यह है कि भारत ने केवल पानी छोड़ा, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक है। भारत ने पश्चिमी नदियों का अधिकांश जल उपयोग पाकिस्तान को दिया और उसके सिंचाई ढांचे के विकास में भी आर्थिक सहयोग किया। बदले में भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित सिंचाई, घरेलू उपयोग और जलविद्युत परियोजनाएं बनाने का अधिकार मिला, लेकिन पानी के प्राकृतिक प्रवाह को रोकने का अधिकार नहीं मिला। संधि के तहत स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया, जिसके माध्यम से दोनों देश नियमित बैठकें करते थे, परियोजनाओं की जानकारी साझा करते थे और विवादों का समाधान बातचीत से निकालने की कोशिश करते थे। यही व्यवस्था छह दशकों तक इस संधि की सबसे बड़ी ताकत रही।

इसलिए बदली भारत की नीति

पिछले तीन दशकों में उरी, पठानकोट, पुलवामा और पहलगाम जैसे आतंकी हमलों ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को लगातार बढ़ाया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देता है और दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय समझौतों का लाभ भी उठाता है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पहली बार स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकवाद और सहयोग साथ-साथ नहीं चल सकते। इसके बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने, जल संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान पर रोक लगाने और संयुक्त बैठकों को बंद करने जैसे कदम उठाए गए। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय और स्थायी कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक यह नीति जारी रहेगी।

इसलिए परेशान है पाकिस्तान

पाकिस्तान की लगभग 80 प्रतिशत कृषि सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। पंजाब और सिंध प्रांत की खेती, खाद्यान्न उत्पादन तथा करोड़ों लोगों की आजीविका इसी जल पर आधारित है। यही कारण है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विदेश मंत्री इसहाक डार और पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी।

हालांकि वास्तविकता यह भी है कि भारत के पास फिलहाल इतनी भंडारण क्षमता नहीं है कि वह पश्चिमी नदियों के पूरे जल प्रवाह को लंबे समय तक रोक सके। इसलिए वतर्मान रणनीति पानी रोकने की नहीं, बल्कि संधि के तहत मिलने वाली प्रशासनिक और तकनीकी सुविधाओं को स्थगित करने की है।

क्या भारत अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ रहा है?

पाकिस्तान का कहना है कि सिंधु जल संधि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसे कोई भी पक्ष एकतरफा निलंबित नहीं कर सकता। दूसरी ओर, भारत का तर्क है कि किसी भी द्विपक्षीय समझौते की नींव पारस्परिक विश्वास पर टिकी होती है। यदि एक पक्ष लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है और दूसरे देश की सुरक्षा को चुनौती देता है, तो इसे परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन माना जा सकता है। भारत का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी देश की सवोच्च प्राथमिकता होती है और ऐसे में उपलब्ध कानूनी एवं रणनीतिक विकल्पों पर पुनर्विचार करना उसका अधिकार है। यही भारत की वर्तमान कूटनीतिक दलील का आधार है।

पानी बन रहा है रणनीतिक शक्ति

इक्कीसवीं सदी में पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि रणनीतिक संपत्ति भी बनता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी, घटते भूजल स्तर और अनियमित मानसून ने जल को भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक संसाधनों में शामिल कर दिया है। भारत के लिए भी यह अवसर है कि वह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पश्चिमी नदियों पर अपने वैध अधिकारों का बेहतर उपयोग करे। जलविद्युत परियोजनाओं, सिंचाई और जल प्रबंधन में निवेश बढ़ाकर ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास को नई गति दी जा सकती है।

आगे की राह

भारत के सामने चुनौती दोहरी है। एक ओर उसे आतंकवाद के खिलाफ कठोर संदेश देना है, तो दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय मंच पर जिम्मेदार और कानून का सम्मान करने वाले राष्ट्र की छवि भी बनाए रखनी है। इसलिए हर कदम कानूनी, तकनीकी और कूटनीतिक रूप से मजबूत होना चाहिए। दूसरी ओर, पाकिस्तान के लिए भी यह आत्ममंथन का समय है। यदि वह आतंकवाद को विदेश नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तो उसके प्रभाव केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जल, व्यापार, कूटनीति और क्षेत्रीय सहयोग जैसे सभी क्षेत्रों पर पड़ेंगे।

सारांश यह है कि सिंधु जल संधि छह दशकों तक भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद का सबसे मजबूत पुल रही। लेकिन बदलते सुरक्षा परिदृश्य ने इसकी राजनीतिक और रणनीतिक भूमिका को पूरी तरह बदल दिया है। आज यह केवल पानी का समझौता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। भारत का संदेश स्पष्ट है कि आतंकवाद और सामान्य संबंध एक साथ नहीं चल सकते। वहीं, यह भी उतना ही आवश्यक है कि जल जैसे जीवनदायी संसाधन को अनावश्यक संघर्ष का माध्यम बनने से बचाया जाए। यदि भविष्य में आतंकवाद समाप्त होता है और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल होता है, तो सिंधु की धाराएं फिर सहयोग और स्थिरता की प्रतीक बन सकती हैं।

कर्मकारों के व्यक्तित्व विकास पर फोकस, भिलाई में प्रशिक्षण का किया गया शुभारंभ

वित्त मंत्री ओमप्रकाश चौधरी लाइव जुड़े, कहा – कर्मचारी ही व्यापार की असली ताकत

नई दृष्टिबिंदु /भिलाई

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भिलाई इकाई, हिंदू जागरण समिति और स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त तत्वावधान में "कर्मकार व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण" का शुभारंभ महोत्सव मंगलवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी, प्रतिष्ठान संचालक और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए।

मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी लाइव माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था या व्यापार की वास्तविक शक्ति उसके कर्मकार होते हैं। यदि कर्मचारियों का व्यक्तित्व, कौशल और कार्य संस्कृति विकसित होगी तो व्यापार स्वतः नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। उन्होंने इस पहल को व्यापारी समाज के लिए उपयोगी बताया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य: विशेष अतिथि प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ संयोजक सुभाष अग्रवाल ने कहा कि ग्राहक व्यवहार, सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन, टीम वर्क, कार्य के प्रति जिम्मेदारी, व्यक्तित्व विकास और व्यावसायिक अनुशासन पर फोकस करना ही इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसका मकसद व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मकारों और स्टाफ की कार्यकुशलता, संवाद कौशल और ग्राहक सेवा क्षमता को बेहतर बनाना है।

चेम्बर महामंत्री अजय भसीन ने प्रशिक्षण शिविर की रूपरेखा और इससे होने वाले लाभों की जानकारी देते हुए सभी व्यापारियों से अपने कर्मचारियों को इसमें भेजने की अपील की।

कार्यक्रम में हिंदू जनजागृति समिति के जिला सह समन्वयक अभिजीत अरविंद पोलके ने स्वभाव दोष पर व्याख्यान दिया। वहीं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के नवीन पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में बंसी अग्रवाल, उद्योग चेम्बर अध्यक्ष जे.पी. गुप्ता, सी.ए. चेयरमैन सुखदेव राठी, महिला चेम्बर अध्यक्ष सुमन कनोजे, दिनेश पाटिल, सिंधी साहित्य अकादमी प्रदेश अध्यक्ष सुषमा जेठानी सहित अनेक चेम्बर पदाधिकारी और सामाजिक प्रमुख उपस्थित थे। मंच संचालन सुनील मिश्रा ने किया।

खास खबर

भिलाई निगम में 2,878 नियमितीकरण प्रकरण लंबित, विधानसभा में विधायक रिकेश ने उठाया मुद्दा

सरकार ने माना– हजारों आवेदन प्रक्रियाधीन, दस्तावेजों की कमी और जांच से हो रही देरी

नई दृष्टिबिंदु /भिलाई

वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने विधानसभा मानसून सत्र के चतुर्थ दिवस भिलाई नगर निगम में लंबित नियमितीकरण प्रकरणों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने सरकार से लंबित आवेदनों, देरी के कारणों और प्रक्रिया पूरी करने की समय–सीमा पर जवाब मांगा। विधायक रिकेश सेन ने पूछा कि पिछले तीन वर्षों में नियमितीकरण के कितने आवेदन लंबित हैं। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि फाइलों पर अंतिम निर्णय क्यों नहीं हो रहा। नियमितीकरण प्रक्रिया जारी है या स्थगित कर दी गई है। साथ ही प्रक्रिया पूरी करने की निश्चित समय–सीमा बताने की मांग की।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 2,878 नियमितीकरण प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। सरकार के अनुसार अभिलेखों की जांच में समय लग रहा है। आवश्यक दस्तावेजों की कमी भी प्रमुख कारण है। कई मामलों में स्थल निरीक्षण लंबित है। इन्हीं कारणों से अंतिम निर्णय में देरी हो रही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण प्रक्रिया स्थगित नहीं की गई है। सभी प्रकरण प्रचलित कानून और नियमों के अनुसार निराकृत किए जा रहे हैं। नियमितीकरण प्रकरणों के निराकरण के लिए अलग समय–सीमा निर्धारित नहीं है। सभी मामलों का नियमानुसार और यथाशीघ्र निराकरण किया जा रहा है।

सुपेला भिलाई पशु चिकित्सालय के जर्जर भवन पर विधायक सेन ने किया सवाल

नई दृष्टिबिंदु /भिलाई

छत्तीसगढ़ विधानसभा के चतुर्थ दिवस वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने सुपेला भिलाई स्थित पशु चिकित्सालय के जर्जर भवन का मामला प्रमुखता से उठाया। उन्होंने ध्यानाकर्षण के जरिए इस अहम विषय पर सरकार से सीधे सवाल किए। विधायक ने पूछा कि क्या अत्यंत क्षतिग्रस्त हो चुके इस भवन के जीर्णोद्धार या नवीन निर्माण की कोई योजना है? उन्होंने अस्पताल में ऑपरेशन रूम, डॉक्टर रूम और शल्य चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग भी की। खाली पदों पर पशु चिकित्सा सहायक विशेषज्ञों की तत्काल पदस्थापना का आग्रह किया।

आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने सदन में स्थिति स्पष्ट करते हुए स्वीकार किया कि उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला दुर्ग द्वारा नवीन भवन निर्माण का प्रस्ताव मिला है। 10 अप्रैल 2026 को प्राप्त यह प्रस्ताव वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। हालांकि, विभागीय मंत्री ने नए संसाधनों और पदों की वृद्धि के संबंध में कोई भी निश्चित समय–सीमा बताने में असमर्थता जताई।

भिलाई में कॉलोनाइजरों की धोखाधड़ी पर विधायक रिकेश के सवाल पर वित्त मंत्री का बड़ा खुलासा

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भिलाई नगर निगम क्षेत्र में निजी कॉलोनाइजरों द्वारा आम जनता से की जा रही धोखाधड़ी का मामला उठाया। विधायक सेन ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान सरकार से पूछा कि भिलाई में कई कॉलोनाइजरों ने प्रोजेक्ट पूरा किए बिना ही लोगों से पूरी रकम वसूल ली है, लेकिन न तो उन्हें मकानों का पजेशन (आधिपत्य) दिया जा रहा है और न ही पैसे वापस किए जा रहे हैं। विधायक रिकेश सेन ने डिफॉल्टर कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सरकार की काययीजना पर तीखे सवाल दागे।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी का जवाब : रेरा में दर्ज हुए 14 मामले

इस मुद्दे पर विभागीय जवाब देते हुए सूबे के वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने सदन को बताया कि विगत तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण कार्यालय में दुर्ग जिला अंतर्गत मकान का आधिपत्य सौंपे जाने के संबंध में कुल 14 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रकरणों में से 13 मामलों में रेरा प्राधिकरण द्वारा अंतिम आदेश जारी किया जा चुका है। केवल एक मामला प्राधिकरण के समक्ष सुनवाई और निर्णय के लिए प्रक्रियाधीन है।

उन्होंने बताया कि रेरा के नियमों के अनुसार स्थानीय निकायवार पृथक से प्रकरण दर्ज नहीं किए जाते हैं। हितग्राहियों के हितों की रक्षा के लिए भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 11, 17, 18 एवं 31 में कड़े उपबंध मौजूद हैं। पीड़ित हितग्राही धारा–31 के तहत रेरा प्राधिकरण के समक्ष अपनी शिकायत या परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं।

पीड़ितों को पैसा वापस दिलाने या मकान का पजेशन दिलाने के लिए रेरा द्वारा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सुनवाई कर गुणदोष के आधार पर अर्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत आदेश पारित किया जाता है। विधायक रिकेश सेन द्वारा दोषी कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर संपत्ति कुर्क करने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कानूनी स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि रेरा अधिनियम, 2016 के तहत प्राधिकरण को सीधे एफआईआर दर्ज कराने का उपबंध नहीं है। मंत्री ने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर धारा–60, 61 एवं 63 के तहत सुनवाई के बाद जुर्माना (शास्ति) लगाने का क्षेत्राधिकार रेरा को है। इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में क्रियान्वयन अधिकारी को सिविल कोर्ट की डिक्री की भांति कार्रवाई करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। यह एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए इसके लिए कोई निश्चित समय–सीमा तय नहीं की जा सकती।

मुद्दे की बात

10 मिनट में सामान मिल सकता है शान्ति नहीं

डॉ.सोनाली चक्रवर्ती के साथ

मेरी एक सहेली ने मुझे कल बताया कि– " कल मैने सब्जी चढ़ाने के बाद देखा कि मेरे घर पर हल्दी नहीं है तो मैने फटाफट ब्लिंकिट पर ऑर्डर कर दिया" मैंने उससे पूछा–" हल्दी से सब्जी में ऐसा कोई बदलाव तो नहीं आ जाता तू बिना हल्दी के बना लेती? " उसका कहना था –"जब ब्लिंकिट है तो मैं क्यों ना मंगवाऊं? "

मैंने कहा –"सिर्फ हल्दी मंगवाने से तो नहीं मिलता 200/– का सामान मंगाना पड़ा होगा ना? " उसने लापरवाही से कहा –"हां कुछ–कुछ मँगवाना था भी और कुछ चीजें यूं ही जोड़ दी जो कभी ना कभी तो काम आ ही जाएंगी लेकिन हल्दी तो मिल गई ना "

दूसरा किस्सा : रात के 10:30–11:00 बजे मैं अपने घर के सामने वाली सड़क पर टहल रही थी तो मैंने देखा मेरे पड़ोस की बच्ची बाहर आई और तभी डिलीवरी बॉय आया और उसे कुछ सामान दिया उसने मुझे अभिवादन किया तो मैं पूछ लिया –"सब ठीक तो है ना इस समय सामान मंगवा रहे है" उसका कहना था–जी पढ़ते–पढ़ते मुझे बोर लग रहा था तो चिप्स खाने का मन हो गया इसलिए मैने चिप्स मंगा लिया"

फिर वही बात कि चिप्स के साथ 200 का सामान तो मंगवाना पड़ा ही होगा! उस समय से मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई की जरूरत का सामान 10 मिनट में मिले इस सोच के तहत हमने डिलीवरी वाले लड़कों को मानो यूं ही परेशान करने का सोच लिया। क्या इसमें हमारे धैर्य की कमी नहीं है। बरसों बरस से गृहनियाँ गृहस्थी जमा के घर संसार के काम कर रहीं हैं। लिस्ट बनाकर जरूर के हिसाब से राशन लाया जाता है।

बहुत पुरानी बात नहीं कि अपनी अपनी पड़ोसनों से छोटी–मोटी घरेलू चीज मांग कर भी काम पूरा किया जाता था और फिर उन्हें वापस करने के नाम पर भी जाकर कुछ और स्नेहिल पल बिताए जाते थे। अब अपने–अपने खोल में सिमटे हुए लोग डिलीवरी बॉय के भरोसे सड़कों को दुर्घटना क्षेत्र बना रहे हैं। मैं सच में सोचने पर मजबूर हो रही थी कि इंटरनेट की दुनिया नहीं होती तो हम कहां होते। आखिर भारत में इंटरनेट सेवाएं कब से शुरू हुई।

गूगल से प्राप्त जानकारी के अनुसारभारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को राज्य के स्वामित्व वाली विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL) द्वारा शुरू की गई थी। उस समय, देश में अंतर्राष्ट्रीय संचार पर वीएसएनएल का एकाधिकार था और इस क्षेत्र में निजी उद्यम की अनुमति नहीं थी। भारत में मोबाइल सेवाओं की शुरुआत 31 जुलाई 1995 को हुई थी।

इसी दिन देश की पहली मोबाइल कॉल पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु और केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम के बीच की गई थी। यह सेवा 'मोदी टेल्स्ट्रा' कंपनी द्वारा शुरू की गई थी? उस समय मोबाइल से कॉल करना बेहद महंगा था और इनकमिंग कॉल के लिए भी शुल्क देना पड़ता था! भारत में ऑनलाइन शॉपिंग को असली पहचान और बूम फ्लिपकार्ट की शुरुआत के बाद मिला, जिसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने 2007 में शुरू किया था। शुरुआत में इस पर भी किताबें ही बेची जाती थीं। मोबाइल ऐप्स का दौर 2010 के बाद स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट के आने के बाद ही हुआ।

2013 में Amazon ने भारत में कदम रखा और इसके साथ ही मीशो, स्नैपडील और मिंत्रा जैसी कंपनियों ने अपने डेडीकेटेड मोबाइल शॉपिंग ऐप्स लॉन्च किए, जिससे देश के छोटे शहरों तक ऑनलाइन शॉपिंग आम हो गई।

यह सभी समाचार अच्छे हैं। इससे बहुत सी सुविधा हुई। छोटे उद्योगों को अपने काम पूरे देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का अवसर प्राप्त हुआ। गृहणियों और खास तौर पर बुजुर्गों को अपना सामान,दवाइयां, राशन आदि घर बैठे मिलने लगा। लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। जरूरत के समान के साथ हमने जाने कब छोटे–मोटे सामान जो हम आते जाते खरीद सकते हैं उनकी डिलीवरी भी घर तक लाने के लिए ऐप्स पर बुकिंग करने लगे और सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ने लगी।

भारत में ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक कॉमर्स (जैसे सामान घर तक पहुंचाने वाली सेवाएं) के तेजी से बढ़ने के कारण डिलीवरी वर्कर्स (Gig Workers) के सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके मुख्य कारण और उससे जुड़े पहलू है समय का अत्यधिक दबाव ग्राहकों तक जल्दी सामान पहुंचाने और कंपनियों के कड़े लक्ष्यों (Targets) को पूरा करने के चक्कर में डिलीवरी राइडर्स अक्सर तेज और खतरनाक ड्राइविंग करते हैं।

अपनी दैनिक आय (Daily Earnings) को बढ़ाने के लिए कई वर्कर हफ्ते में 70 घंटे से अधिक काम करते हैं, जिससे वे अत्यधिक थकान और तनाव का शिकार हो जाते हैं।

खराब ट्रैफिक और सड़क की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। हमारे शहरों में भारी ट्रैफिक, गड्ढे, जलभराव और खराब सड़कें डिलीवरी करने वालों के लिए दोपहिया वाहनों पर संतुलन बनाना बेहद खतरनाक बना देती है। वाहन के रखरखाव का पूरा खर्च राइडर पर होता है, जिससे कई बार पुरानी या खराब हालत की गाड़ियों (जैसे ब्रेक फेल होना) के साथ उन्हें सड़क पर उतरना पड़ता है।

यह सुखद है कि कुछ ही दिन पहले बढ़ते हादसों और वर्कर यूनियनों के विरोध को देखते हुए, भारत सरकार और श्रम मंत्रालय ने त्वरित वाणिज्य (Quick Commerce) कंपनियों को उनके विज्ञापनों और ऐप से '10–मिनट डिलीवरी' के दावों को हटाने का निर्देश दिया है। सरकार और स्थानीय प्रशासन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स (जैसे [Blinkit, Zepto, Swiggy]) पर राइडर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सामाजिक सुरक्षा (Social Security) और दुर्घटना बीमा देने के लिए कड़े नियम लागू करने पर जोर दे रहे हैं।

सरकार तो अपना काम कर ही रही है हमारा नागरिक बोध भी जागना चाहिए। अपने बेसिर पैर के जरूरतों के लिए हमें देश के संसाधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी पेट्रोल बचाने पर जोर दे रहे हैं हम सब भी विश्व युद्ध की आशंकाओं वाले समाचारों से अनभिज्ञ नहीं है। उस समय हम नींबू, हल्दी और चिप्स मंगवाने के लिए इन एप्स का इस्तेमाल न करें तो बेहतर जिससे दवाइयां और जीवन रक्षक चीज समय पर पहुंचने के लिए हमारे पास पर्याप्त ईंधन रहे।

एक अलग चर्चा का विषय यह है कि जब जो चाहिए वह तभी हासिल करने की इच्छा क्या हमारे मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों को भी प्रभावित नहीं कर रही? यदि आपके पास है कोई भी आईडिया तो हमें अवश्य बताएं।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, स्कूटी–ट्रैक्टर की टक्कर में 4 की मौत

नई दृष्टिबिंदु /भिलाई-3

भिलाई–3 थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक 8 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 मासूम बच्चियां शामिल हैं।

मामा के घर जा रहा था परिवार : दुर्ग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अमृत निर्मलकर, 28 वर्ष, स्कूटी चला रही थीं। उनके साथ कुल 5 लोग बसंत विहार, रायपुर स्थित अपने मामा के घर जा रहे थे। रास्ते में राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े ट्रैक्टर क्रमांक CG 07 NA 0930 के पीछे स्कूटी तेज गति से जा टकराई। ट्रैक्टर में ऑक्सीजन सिलेंडर लदे हुए थे।

घटना में 4 की मौत, 1 घायल : इस टक्कर में स्कूटी सवार चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में अमृत निर्मलकर 28 वर्ष, निवासी भिलाई–3, लक्ष्मी निर्मलकर 26 वर्ष, यासना 7 वर्ष और डाली 4 वर्ष शामिल हैं। जबकि 8 वर्षीय भावेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने ट्रैक्टर किया जप्त : सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुपेला मर्चुरी में रखवाया है। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जप्त कर लिया है और चालक भोला यादव को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण की विवेचना शुरू कर दी है। हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है।

बेमेतरा: ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, एक दिन में 19 वाहन चालकों पर कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु /बेमेतरा

एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देश पर जिले भर में चला सघन चेकिंग अभियान

सड़क सुरक्षा को लेकर बेमेतरा पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल IPS के निर्देश पर जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत सिर्फ एक दिन में पुलिस ने 19 वाहन चालकों का चालान काटा और 8,200 रुपये समन शुल्क वसूला। कार्रवाई के दौरान तेज रफ्तार से वाहन चलाने, बिना हेलमेट बाइक चलाने, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने, जरूरी दस्तावेज साथ न रखने और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसा गया।

बेमेतरा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों, नाबालिगों को वाहन सौंपने वालों और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि सड़क पर निकलते समय हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाएं और मोबाइल का उपयोग न करें। पुलिस का कहना है कि "कुछ मिनट की लापरवाही आपकी जान भी ले सकती है और भारी जुर्माना भी लगवा सकती है। सुरक्षित सफर ही सुरक्षित जीवन है।"

दुर्ग पुलिस ने शुरू की "पिंक पेट्रोलिंग", महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिले में उतारीं 14 विशेष टीमें

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने दिखाई हरी झंडी, स्कूल–कॉलेज, बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर होगी सतत निगरानी

नई दृष्टिबिंदु /भिलाई-दुर्ग

महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस ने बुधवार को "पिंक पेट्रोलिंग" अभियान की शुरुआत की। पुलिस कंट्रोल रूम, सेक्टर–06 भिलाई से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर 14 विशेष पिंक पेट्रोलिंग टीमों को जिलेभर के लिए रवाना किया।

14 टीमें, 24x7 सतर्क

जिले के 13 थाना क्षेत्रों और 1 रक्षा टीम को मिलाकर कुल 14 पिंक पेट्रोलिंग टीमें बनाई गई हैं। हर टीम में 4 महिला–पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और प्रत्येक टीम का नेतृत्व एक पीएसआई प्रभारी करेगा। ये टीमें महिला, छात्राओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के साथ भीड़भाड़ और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त करेंगी।

पिंक पेट्रोलिंग के प्रमुख काम

1. **स्कूल–कॉलेज फोकस:** स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के खुलने और बंद होने के समय नियमित पेट्रोलिंग कर छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
2. **त्वरित कार्रवाई:** महिला सुरक्षा संबंधी शिकायतों और डायल–112 से मिली सूचनाओं पर तत्काल मौके पर पहुंचकर मदद और कानूनी कार्रवाई करना।
3. **सार्वजनिक स्थलों पर गश्त:** बाजार, मॉल, पार्क, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नियमित गश्त।
4. **मनचलों पर नजर:** असामाजिक तत्वों और संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखकर वैधानिक कार्रवाई करना।
5. **जागरूकता:** महिला हेल्पलाइन 1091, आपात सेवा 112 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में आम लोगों को जागरूक करना।

अधिकारी मौजूद रहे

इस अवसर पर एएसपी शहर सुखनंदन राठौर, एएसपी ग्रामीण मनीशंकर चंद्रा, एएसपी यातायात ऋचा मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक हर्षित मेहर, सत्य प्रकाश तिवारी, डीएसपी भारती मरकाम और डीएसपी आकर्षि कश्यप सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। अभियान के समन्वय और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी डीएसपी भारती मरकाम और डीएसपी आकर्षि कश्यप को सौंपी गई है।

पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि छेड़छाड़, उत्पीड़न या किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत डायल–112, महिला हेल्पलाइन 1091 या नजदीकी थाने को दें। पुलिस ने कहा कि महिला सुरक्षा सवीच्च प्राथमिकता है और हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

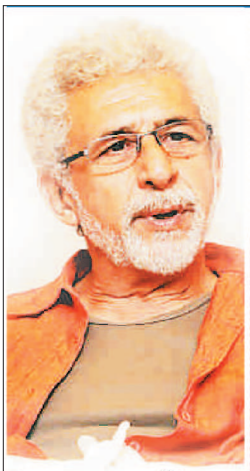

एक्शन ड्रामा फिल्म 'ओम' में धनुष के साथ नजर आएंगे नसीरुद्दीन शाह

दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह अपनी नई रिलीज हुई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की कामयाबी को लेकर खुश हैं। इस बीच खबर है कि वह धनुष की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म 'ओम' में नजर आने वाले हैं। वह आधिकारिक तौर पर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए हैं, जिससे 26 साल बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी हो रही है। यह एक बड़े बजट का प्रोडक्शन है जिसे दो-भागों वाली एक्शन ड्रामा फिल्म के तौर पर बनाया जा रहा है। इसका निर्देशन राजकुमार पेरियासामी कर रहे हैं, जिन्हें 'अमरन' के लिए काफी तारीफें मिली थीं।

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर नसीरुद्दीन शाह की एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा 'ओम की दुनिया में एक दमदार एंट्री। दिग्गज नसीरुद्दीन इस मेगा फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। 16 अक्टूबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में आ रही है।'

20 साल पहले तमिल में किया था काम

आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह ने कमल हासन की फिल्म 'हे राम' (2000) में शाहरुख खान के साथ महात्मा गांधी की भूमिका निभाई थी। यह उनकी आखिरी तमिल फिल्म थी। फिल्म से जुड़ सकते हैं ममूटी नसीरुद्दीन शाह के जुड़ने से अब 'ओम' की कास्ट काफी मजबूत हो गई है, जिसमें धनुष मुख्य भूमिका में हैं। साई पल्लवी और श्रीलीला को फीमेल लीड के तौर पर कास्ट किया गया है। फिल्म में मलयालम अभिनेता ममूटी के भी एक अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। 'ओम चैप्टर 1: उधिरम- द ब्लड वुड' 16 अक्तूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

'सतलुज' को ओटीटी से हटाए जाने पर बोलीं नीरू बाजवा

पंजाबी एक्ट्रेस नीरू बाजवा ने सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने पर निराशा जाहिर की है। फिल्म को रिलीज होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही हटा दिया गया था। नीरू ने दिलजीत के साथ कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने कहा कि दर्शकों को यह चुनने का हक है कि वे किसी फिल्म का समर्थन करना चाहते हैं या उसकी आलोचना करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दर्शकों को यह जानने का हक है कि फिल्म को अचानक ओटीटी प्लेटफॉर्म से क्यों हटाया गया।

नीरू ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मैंने 'सतलुज' देखी, भावनाएं निश्चित रूप से जागृत हुईं। एक फिल्म मनोरंजन से कहीं बढ़कर है। यह उसके निर्माताओं की आवाज, उनका जुनून, उनका सच और बरसों की कड़ी मेहनत है। किसी के पास भी बिना जवाबदेही के उसे दबाने की ताकत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग किसी फिल्म का समर्थन करें या उसकी आलोचना, यह उनका फैसला होना चाहिए। दर्शकों से यह विकल्प छीनना गलत है। हमें इसे देखने, खुद सोचने और यह तय करने का हक है कि हमारे लिए इसका क्या मतलब है। अगर 'सतलुज' को हटाया गया है तो जनता को स'चाई जानने का हक है। हमें स्पष्टीकरण चाहिए, खामोशी नहीं। पारदर्शिता कोई विशेषाधिकार नहीं है; यह एक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि पंजाबी होने के नाते, उन्हें सवाल पूछने का हक है अगर उनकी मातृभूमि की कहानियों को उनसे छिपाया जाता है। अभिनेत्री ने कहा कि हम कुछ खास नहीं मांग रहे हैं। हम स'चाई, निष्पक्षता और फिल्म को अनुभव करने और अपनी राय बनाने की आजादी मांग रहे हैं। हमारी आवाज मायने रखती है। हमारी कहानियां मायने रखती हैं और स'चाई मायने रखती है। मंगलवार को नीरू ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उन्हें यह बहुत गलत लगा कि 'सतलुज' को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया, जबकि उन्हें फिल्म देखने का मौका भी नहीं मिला था। उन्होंने लिखा कि पंजाबी कलाकार के तौर पर मुझे गर्व है, लेकिन 'सतलुज' को हटाए जाने से निराशा महसूस हुई। हमारी संस्कृति और पहचान को दर्शाने वाली कहानियां देखे जाने के लायक हैं, दबाए जाने के लायक नहीं। यह फैसला हमारे समुदाय के लिए अन्यायपूर्ण और दिल तोड़ने वाला है।

सेंसरशिप के खिलाफ लंबी लड़ाई के बाद, 'सतलुज' आखिरकार जी-5 पर रिलीज हुई। हालांकि, रिलीज के सिर्फ 2 दिन बाद ही भारत में फिल्म को हटा दिया गया।

लॉस एंजिल्स में भाषा से जुड़ी चुनौतियों पर बोलीं सना सईद

सुपरहिट फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में शाहरुख खान की बेटी 'अंजलि' का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली अभिनेत्री सना सईद ने सोशल मीडिया पर अपना एक अनुभव साझा किया। दरअसल, उन्होंने विदेश में रहने के दौरान भाषा, उच्चारण और संवाद से जुड़ी कठिनाइयों के बारे में खुलकर बात की। सना सईद आज लॉस एंजिल्स में रहती हैं और अपने करियर और जीवन को नए तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने अमेरिका पहुंचने के शुरुआती दिनों का एक दिलचस्प अनुभव बताया। सना ने बताया, 'साल 2016 में मैं पहली बार पढ़ाई के लिए लॉस एंजिल्स आई थी। इस दौरान मुझे रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातों में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे अमेरिका में लंबे समय तक रहना है, तो मुझे अपने बातचीत करने के तरीके पर काम करना होगा, क्योंकि सुना जाना सबसे जरूरी है। इसके बाद मैंने अपने उच्चारण और बोलने के तरीके पर ध्यान देना शुरू किया और इसके लिए ट्रेनिंग भी ली।'' सना ने बताया कि यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। किसी नए देश में जाकर वहां की भाषा के अनुसार खुद को ढालना बिल्कुल एक नई भाषा सीखने जैसा होता है। इसमें समय, मेहनत और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, ''कई लोग सोचते हैं कि उच्चारण बदलना बहुत आसान है, लेकिन असल में इसके पीछे बहुत मेहनत और आत्मविश्वास की जरूरत होती है।''

काजल अग्रवाल ने खूबसूरत दिखने के दबाव पर रखी राय

काजल अग्रवाल ने अभिनेत्रियों के परफेक्ट दिखने के दबाव को लेकर बात की है। उनका मानना है कि आज की एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में आने के लिए ज्यादा कड़ी जांच-परख का सामना करना पड़ता है। उन्होंने माना कि उन्हें उन युवा एक्ट्रेस के लिए बुरा लगता है जो इंडस्ट्री के खूबसूरती के पैमानों से जूझ रही हैं।

पहले दबाव कम था

जूम के साथ बातचीत में काजल ने खूबसूरत दिखने के दबाव को लेकर कहा 'समय बहुत अलग था। सोशल मीडिया नहीं था। बाहरी तौर पर एक्स्ट्रा जजमेंट नहीं होते थे। ऐसे कोई एयरपोर्ट लुक नहीं थे, जिनके लिए आपको सफाई देनी पड़े। आप बस जैसे हैं, वैसे ही रह सकते थे और किसी कमरे या एयरपोर्ट में आराम से जा सकते थे। पूरी तरह तैयार होकर ट्रैवल करना आसान नहीं है। शुक्र है कि उस समय मुझे इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ा।'

युवा लड़कियों के लिए बुरा लगता है

काजल ने आगे कहा 'फिल्ममेकर्स की तरफ से जजमेंट जरूर आते थे, जैसे वे चाहते थे कि मैं मोटी या पतली दिखूं या कुछ और। ऐसी बातें होती थीं। मगर मुझे लगता है कि तब भी चीजें आसान थीं। तब इतना क्रूर माहौल नहीं था। इसलिए मुझे अभी की युवा लड़कियों के लिए बुरा लगता है। मुझे सच में उम्मीद है कि वे अपनी जगह बना पाएंगी।'

'ना' कहना सीखना जरूरी है

काजल ने यह भी कहा कि उनमें हमेशा उन स्थितियों से बाहर निकलने का आत्मविश्वास रहा है, जिनमें वे सहज नहीं थीं। उन्होंने कभी भी सिर्फ मौके पाने के लिए 'हां' कहने का दबाव महसूस नहीं किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर बात पर सहमत होने के बजाय 'ना' कहना सीखना कहीं ज्यादा जरूरी है। काजल अभी अपनी अपकमिंग फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' की रिलीज का इंतजार कर रही हैं। चेतन डीके के निर्देशन में बनी इस फिल्म में श्रेयस तलपड़े भी मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म पेस्टिसाइड (कीटनाशक) वाली खेती और समाज पर इसके असर को दिखाती है। यह 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

राम कपूर का छलका दर्द

गौतमी और मैंने भी इंडस्ट्री में झेला उम्र का भेदभाव

टीवी के लोकप्रिय अभिनेता राम कपूर ने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं और दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल किया है। वह अक्सर मनोरंजन जगत के उस सच पर खुलकर बात करते दिखते हैं, जिसके बारे में कलाकार बोलने से बचते नजर आते हैं। इस कड़ी में राम कपूर ने बताया कि इंडस्ट्री में उम्र बढ़ने के साथ कलाकारों को किस तरह नजरअंदाज किया जाता है। साथ ही बताया कि उनकी पत्नी और अभिनेत्री गौतमी कपूर भी इसी तरह के दौर से गुजर चुकी हैं।

राम कपूर ने यह खुलासा नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' के दौरान आकांक्षा चमोला से बातचीत में किया। दरअसल, शो में आकांक्षा चमोला ने राम कपूर से कहा कि वह जल्द ही अपने पति गौरव खन्ना से अलग रहकर अपनी नई शुरुआत करने वाली हैं। ऐसे में उन्हें अपना नया ठिकाना बनाना होगा और करियर को भी नए सिरे से संभालना पड़ेगा। उन्होंने राम से कहा कि इस सफर में उन्हें उनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। आकांक्षा की बात सुनकर राम ने बिना किसी झिझक के उनका साथ देने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह अपनी पूरी टीम को उनकी मदद के लिए लगा देंगे।

बातचीत के दौरान आकांक्षा ने मनोरंजन इंडस्ट्री की एक बड़ी समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि यहां कलाकारों की उम्र को लेकर बहुत जल्दी धारणा बना ली जाती है। जैसे ही कोई कलाकार 35 साल की उम्र पार करता है, उसे यह कहकर अलग कर दिया जाता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। इससे कलाकारों के लिए नए मौके कम होने लगते हैं और करियर पर असर पड़ता है। आकांक्षा ने राम कपूर से बात करते हुए कहा, 'आप जानते हैं कि लोग हमारी उम्र को अच्छी नजर से नहीं देखते। दुर्भाग्य से जैसे ही कोई कलाकार 35 साल का होता है, उसे यह कहकर अलग कर दिया जाता है कि वह अब बहुत उम्रदराज हो गया है। मुझे इस दुनिया की ज्यादा समझ नहीं है। मैं जितना कर सकती थी, उतना किया है। अब उम्मीद है कि आगे भी काम मिलता रहे, ताकि मैं अपनी जिंदगी सुरक्षित बना सकूं।' आकांक्षा की बातें सुनकर राम कपूर ने कहा कि उनकी स्थिति उन्हें अपनी पत्नी गौतमी कपूर की याद दिलाती है। उन्होंने बताया कि गौतमी भी अपने करियर में ऐसे ही दौर से गुजरी हैं और वह इस दर्द को अच्छी तरह समझते हैं।

राम ने कहा, 'गौतमी और मैंने भी उम्र का भेदभाव झेला है। शुरुआत में गौतमी भी इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरी थीं। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो दौर तुम झेल रही हो, उससे गौतमी भी गुजर चुकी हैं। वह मेरी पत्नी हैं, मेरी दुनिया हैं, मेरा प्यार हैं। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि तुम किस स्थिति में हो। मैं तुम्हारे लिए जितना संभव होगा, उतनी मदद करूंगा।' बता दें कि नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं। शो में आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, सुनीता आहूजा, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, सूफी मोतीवाला, धीरज धूपर, माधुरी जैन ग्रोवर, रियाज अली और वरुण यादव उर्फ लैला जैसे कई चर्चित चेहरे भी शामिल हैं।

पुलिस अधीक्षक ने ली अपराध समीक्षा बैठक, बेसिक और विजिबल पुलिसिंग मजबूत करने के दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और नागरिकों से संवेदनशील व्यवहार पर जोर

पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना और चौकी प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस कार्यप्रणाली की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बेसिक पुलिसिंग और बीट प्रणाली सुदृढ़ करने पर बल

पुलिस अधीक्षक ने बीट प्रणाली को मजबूत कर क्षेत्र में पुलिस की नियमित और प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विजिबल पुलिसिंग पर विशेष ध्यान देने और प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार माइक्रो लेवल कार्ययोजना तैयार कर लागू करने को कहा।

बैठक में थानों के रजिस्टर और अभिलेखों को अद्यतन रखने, निगरानी और गुंडा बदमाशों की सतत चेकिंग तथा किशोर पंजी के प्रभावी संधारण के निर्देश दिए। लंबित मर्ग, गुम इंसान, शिकायत और पुराने आपराधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया। संज्ञेय अपराध वाले मामलों में अपराध कायम कर कारवाई और असंज्ञेय मामलों में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सभी प्रकरणों का तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

तकनीकी साक्ष्य और विवेचना की गुणवत्ता

विवेचना को प्रभावी बनाने के लिए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, साइबर और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का समयबद्ध संकलन करने कहा गया। तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर साक्ष्य आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसडीओपी को विवेचकवार प्रकरणों की नियमित समीक्षा और विवेचना में कमियों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण देने को कहा गया।

जनसंपर्क और डायल-112 की समीक्षा : पुलिस कर्मियों को आम नागरिकों के प्रति शिष्ट और संवेदनशील व्यवहार अपनाने तथा थाने आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। डायल-112 के रिस्पॉन्स टाइम की नियमित समीक्षा कर आपातकालीन सेवाओं को और चुस्त करने को कहा गया।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

- आबकारी अधिनियम के तहत जब्त शराब का विधिसम्मत नष्टीकरण और मालखाना में जब्त सामग्री की लेबलिंग-सत्यापन सुनिश्चित करें।
- साइबर फ्रॉड के मामलों में त्वरित कारवाई और अज्ञात आरोपी वाले प्रकरणों के लिए विशेष टीम गठित करें।
- होटल, ढाबा, लॉज और सार्वजनिक स्थानों की नियमित चेकिंग करें।
- ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए मुकरता चौक में पीक ऑवर्स में थाने से कम से कम एक कांस्टेबल की ड्यूटी सुनिश्चित करें।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन, नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर किरो, एसडीओपी डोंगरगांव मंजुलता बाज, एसडीओपी डोंगरगढ़ केसरीनंदन नायक, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के.पी. मरकाम, उप पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन एम्ब्रोज कुजूर सहित जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारी और कार्यालयीन स्टाफ उपस्थित थे।

खास खबर

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने नामांकित पार्षदों को दिलाई एल्डरमेन पद की शपथ

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

नगर निगम राजनांदगांव में 8 एल्डरमेन ने ली शपथ

राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने सोमवार को नगर पालिक निगम राजनांदगांव के टाउन हॉल में नगर निगम के नामनिर्दिष्ट (एल्डरमेन) सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले एल्डरमेन में नागेश यदु, करूणा राजपूत, हर्ष रामटेके, सूर्यकांत श्रीवास, मंजु यादव, भीषम देवांगन, कृषि बोरकर और देवाशीष झा शामिल हैं। इस अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव, नगर पालिक निगम अध्यक्ष टोपेन्द्र सिंह पारस वर्मा, कोमल सिंह राजपूत, नगर निगम आयुक्त जीआर मरकाम सहित अन्य पार्षद, अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक उपस्थित थे।

जनपद पंचायत राजनांदगांव की साधारण सभा की बैठक कल, विभागीय कार्यों की होगी समीक्षा

राजनांदगांव। जनपद पंचायत राजनांदगांव की साधारण सभा की बैठक 17 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे जनपद पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है। संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का किया आकस्मिक निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और स्टाफ बढ़ाने के दिए निर्देश

राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने सोमवार को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव का आकस्मिक निरीक्षण कर विभिन्न विभागों और वार्डों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रेडियोलॉजी विभाग में प्रतिदिन होने वाले सीटी स्कैन और सोनोग्राफी की संख्या तथा विभाग की समस्याओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से दो सीटी स्कैन टेक्नीशियन की भर्ती हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कैजुअल्टी वार्ड में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से चर्चा कर चिकित्सा व अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। मरीजों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने कैजुअल्टी वार्ड में दो मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने नियोनेटल वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिलर प्लांट में आवश्यक सुधार और अन्य व्यवस्थाओं के विस्तार के निर्देश दिए। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के समय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. पी.एम. लूका, अधीक्षक डॉ. अतुल देशकर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवातरन तथा डॉ. पवन जेठानी सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर यादव ने साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की

सूर्यघर योजना, पौधरोपण, कुपोषण मुक्ति और एचपीवी वैक्सीनेशन में तेजी के दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रमुख निर्देश

सूर्यघर योजना: कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का परीक्षण शीघ्र पूरा कर पात्र हितग्राहियों के घरों में सोलर पैनल स्थापना में तेजी लाने को कहा। वार्डों और ग्राम पंचायतों में नियमित सूर्यघर सभाएं आयोजित कर जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। बताया कि जिले में अब तक 3 हजार 959 हितग्राहियों के घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं।

कृषि: किसानों को धान की जगह दलहन और तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों की बोआई के लिए प्रोत्साहित करने तथा पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिले में अब तक 61 प्रतिशत बोआई हो चुकी है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग के प्रति जागरूकता लाने को भी कहा।

स्वास्थ्य: एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा में बताया कि अब तक 4 हजार 777 किशोरी बालिकाओं का टीकाकरण हुआ है। स्कूलवार रोस्टर बनाकर अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग, सोनोग्राफी और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मोबाइल से प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने को कहा।

अन्य बिंदु: गिरदावरी कार्य को गंभीरता से करने और पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर कार्ययोजना बनाने के निर्देश, पौधरोपण अभियान के लिए पौधों की उपलब्धता, रोपण स्थल और लक्ष्य तय कर समयबद्ध रोपण सुनिश्चित करने को कहा, सीएम हेल्पलाइन 1076, जन शिकायतें और सुशासन तिहार के आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने ऑनलाइन मॉनिटरिंग के निर्देश, सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के आधार सत्यापन प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश, नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और वर्षा में जलभराव रोकने नालियों की नियमित सफाई के निर्देश, कुपोषण मुक्ति अभियान में कुपोषित बच्चों को सुपोषण श्रेणी में लाने और शत-प्रतिशत कुपोषण मुक्त ग्राम पंचायतों व आंगनबाड़ी केंद्रों को सम्मानित करने के निर्देश, अग्निवीर भर्ती की जानकारी लेकर पिछले वर्ष चयनितों को सम्मानित करने तथा आश्रम-छात्रावासों के नियमित निरीक्षण के निर्देश शामिल हैं।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत दुर्गा प्रसाद अधिकारी, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, प्रेमप्रकाश शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

जनदर्शन : आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण करने के दिए निर्देश

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने सोमवार को कलेक्टोरेट में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं और मांगें सुनीं। जनदर्शन में नामांतरण, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, भू-अर्जन, अवैध अतिक्रमण हटाने, नजूल भूमि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व अभिलेखों में सुधार सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए। नागरिकों ने शासकीय योजनाओं का लाभ और व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं के समाधान के लिए भी आवेदन दिए। कलेक्टर ने सभी आवेदनों का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनदर्शन आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। आमजन अपनी अपेक्षाओं के साथ प्रशासन के पास आते हैं, इसलिए प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण कर नियमानुसार शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पात्र हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए। जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करें और आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने आवेदनों के निराकरण की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए।

राजनांदगांव पुलिस की व्यापक कॉम्बिंग गश्त : 110 पुलिस बल ने 89 असामाजिक तत्वों की चेकिंग की

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

शहर में अपराधियों पर कड़ी नजर, आगे भी जारी रहेगा अभियान

पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में जिला पुलिस ने 13 जुलाई 2026 की रात 9 बजे से देर रात तक शहर क्षेत्र में व्यापक कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया।

अभियान के लिए 5 राजपत्रित अधिकारियों के अंतर्गत 11 निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक सहित कुल 110 पुलिस बल की 4 विशेष टीमें गठित की गईं। इन टीमों ने कोतवाली, बसंतपुर, चिखली और लालबाग थाना क्षेत्रों में एक साथ सघन चेकिंग और तस्दीक की।

गश्त के दौरान गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश, माफी बदमाश, स्थायी वारंटी और अपराध प्रवृत्ति वाले किशोरों के निवास स्थानों पर दबिश दी गई। कुल 89 असामाजिक तत्वों की सघन चेकिंग की गई और उन्हें भविष्य में आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने, समय पर घर में उपस्थित रहने तथा शराब पीकर विवाद न करने की कड़ी समझाइश दी गई।

क्षेत्रवार कार्रवाई :- थाना बसंतपुर: कुवा चौक, नंदई चौक, इंदिरा नगर चौक, क्लब चौक, शिवनगर, बंगाली चॉल में 20 गुंडा/निगरानी बदमाशों की चेकिंग

- चौकी चिखली: सोलाखोली, नवागांव, बापूटोला, स्टेशनपारा, गौरीनगर, मोतीपुर में 25 असामाजिक तत्वों की जांच
- थाना कोतवाली: लखोली सहित अन्य क्षेत्र में 16 गुंडा/निगरानी/माफी बदमाशों की चेकिंग
- थाना लालबाग: पेंड्री बस्ती, पेंड्री अटल आवास में 28 असामाजिक तत्वों की तस्दीक

पुलिस ने स्पष्ट किया कि शहर में सक्रिय सभी असामाजिक तत्वों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर है और किसी भी अवैध/आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने चेतावनी दी कि भविष्य में अपराध में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कॉम्बिंग गश्त आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

विकसित भारत जी राम जी योजना के कार्यों को देखने कबीरधाम पहुची केंद्रीय टीम

नई दृष्टिबिंदु / कबीरधाम

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव पीके शर्मा तथा अवर सचिव राहुल कुमार श्रीवास्तव ने विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को देखने दो दिवसीय प्रवास पर कबीरधाम जिले में पहुँच कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक अग्रवाल ने विकसित भारत जी राम जी योजना के कायी की प्रगति एवं अन्य आवश्यक तैयारियों से केन्द्रीय टीम को अवगत कराया। इतिहास

केंद्रीय टीम द्वारा योजना से जुड़े सभी मैदानी कर्मचारियों की बैठक लेकर योजना के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।गांव की आवश्यकता अनुसार निर्माण कायी की पहचान में ग्रामीणों की भूमिका, कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया, युक्त धारा पोर्टल में कायी की एंट्री, काम की मांग, एनएमएमएस द्वारा ऑनलाइन हाजिरी, समय सीमा में मजदूरी भुगतान की जानकारी, 125 दिनो के रोजगार हेतु ग्रामीणों की मांग पर नए कार्यों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर जानकारी ली गई।

सीईओ जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी ग्राम पंचायतो के लिए पर्याप्त कार्य की स्वीकृत करते हुए रोजगार की मांग अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहे हैं। साथ ही बताया गया कि योजना अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने के मामले में पूर्व की भांति कबीरधाम जिला प्रदेश में लगातार अग्रणी बना हुआ है। जिस पर केंद्रीय टीम द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की।

प्रवास के दौरान केंद्रीय टीम के अधिकारियों ने ग्राम पंचायत रेंगाखारखुर्द में पहुंच कर आंगनबाड़ी भवन का निरीक्षण किया। कार्य की गुणवत्ता, मजदूरी भुगतान, मानव दिवस एवं कार्य से ग्रामीणों को हो रहे लाभ की जानकारी ली गई। ग्राम पंचायत चिखली के तालाब में चल रहे मछली पालन की आजीविका गतिविधियों का अवलोकन

कर हितग्राही से हो रहे लाभ की जानकारी ली। ग्राम पंचायत पोड़ी में सामुदायिक बोरवेल रिचार्ज पिट के कार्य का निरीक्षण कर जानकारी ली गई। ग्राम पोड़ी निवासी हितग्राही रामभजन पिता लतेल के लिए बनाए गए निजी आजीविका डबरी का निरीक्षण किया गया। डबरी की उपयोगिता पर हितग्राही से जानकारी ली गई। हितग्राही द्वारा बताया गया कि डबरी निर्माण से सिंचाई सुविधा का विस्तार हुआ है तथा मत्स्य पालन से आजीविका का नया साधन मिला है।

निरीक्षण के दौरान जनपद पंचायत बोड़ला के ग्राम पंचायत राजानवागांव में विकसित भारत जी राम जी के प्रावधानों के संबंध में मजदूरों, समूह की दीदियों से चर्चा कर अधिकारियों ने योजना के उद्देश्य, ग्राम विकास में भूमिका, ग्रामीणों के आजीविका संवर्धन, रोजगार के अवसर, सामुदायिक सहभागिता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल संवर्धन, कृषि एवं अन्य विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में विस्तृत चर्चा कर जानकारी दी। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों से योजना से संबंधित सुझाव एवं समस्याओं की जानकारी ली गई तथा अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया गया।

केंद्रीय टीम ग्राम पंचायत नेउरगांवखुर्द पहुंचकर विकसित भारत जी राम जी उद्यान का निरीक्षण किया गया। जिसमें फलदार एवं छायादार के 500 से अधिक पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। पौधों के रखरखाव पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान केंद्रीय टीम द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेते हुए पौधारोपण भी किया। केंद्रीय टीम के निरीक्षण के दौरान सीईओ जनपद पंचायत बोड़ला,सहायक परियोजना अधिकारी विकसित भारत जी राम जी, तकनीकी समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी सहित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव स्व सहायता समूह की दीदीयां सहित, मैदानी कमचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

सेवा सेतु पोर्टल से मिला विवाह प्रमाण पत्र, अब शासकीय योजनाओं का लाभ लेना हुआ आसान

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

डिजिटल सुशासन की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण पहल सेवा सेतु पोर्टल आम नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न शासकीय सेवाएं अब घर बैठे सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो रही हैं। इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण विकासखंड साजा की ग्राम पंचायत खुरुसबोड-आर में देखने को मिला।

ग्राम पंचायत खुरुसबोड-आर निवासी श्रीमती हेमिन, पिता संजय यादव एवं नीरज कुमार यादव ने अपने विवाह प्रमाण पत्र के लिए सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन की निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका विवाह प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक जारी कर दिया गया।

विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद अब दंपति के लिए विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं

आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रियाओं का लाभ लेना काफी आसान हो गया है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग महतारी वंदन योजना, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, श्रम कार्ड, बैंकिंग सेवाओं, बीमा, पासपोर्ट, संयुक्त बैंक खाता, नामांकन सहित अन्य शासकीय एवं कानूनी कार्यों में किया जा सकेगा। साथ ही भविष्य में किसी भी वैधानिक अथवा प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान यह उनके वैवाहिक संबंध का आधिकारिक प्रमाण भी रहेगा।

सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूरी हुई। इससे आवेदकों का समय और अनावश्यक खर्च दोनों बचे तथा उन्हें सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह व्यवस्था नागरिकों को डिजिटल माध्यम से बेहतर एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रभावी पहल सिद्ध हो रही है।

हितग्राही की जुबानी

श्रीमती हेमिन ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा- मोर बेटी ल महतारी वंदन योजना के लाभ दिलाय बर, राशन कार्ड, श्रम कार्ड मं नाम जुड़वाय बर अउ आधार कार्ड म पति के नाम जुड़वाय बर विवाह प्रमाण पत्र के जरूरत रहिस। सेवा सेतु पोर्टल के मदद ले जनपद पंचायत साजा के ग्राम पंचायत खुरुसबोड-आर म मोर आवेदन झटपट पूरा होगे अउ मोला समय मं विवाह प्रमाण पत्र मिलगे। एखर सेती मोर सबो जरूरी काम बिना किसी परेशानी के पूरा होवत हे। मैं छत्तीसगढ़ सरकार अउ जिला प्रशासन के प्रति हृदय से धन्यवाद व्यक्त करत हवंव।

सेवा सेतु पोर्टल नागरिकों तक शासन की सेवाओं को सरल, सुगम, पारदर्शी एवं डिजिटल माध्यम से पहुँचाने की दिशा में एक प्रभावी पहल है। यह व्यवस्था न केवल सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ा रही है, बल्कि आम नागरिकों के समय, श्रम और धन की भी बचत सुनिश्चित कर रही है।

हर घर तक पहुंचा स्वच्छ जल, बदली ग्राम राहुद की तस्वीर

खैरागढ़। कभी पेयजल की समस्या से जूझने वाला विकासखंड खैरागढ़ का ग्राम राहुद आज जल जीवन मिशन की बदौलत स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के मामले में एक नई पहचान बना रहा है। घर-घर नल से जल पहुंचने के बाद ग्रामीणों के दैनिक जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को पानी लाने की जिम्मेदारी से राहत मिली है, जिससे वे अपना समय अन्य उपयोगी कार्यों में लगा पा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम राहुद में 60 किलोलीटर क्षमता की उच्च स्तरीय जल टंकी का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही सुदृढ़ पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से गांव के लगभग 300 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अब ग्रामीणों को अपने घरों में ही नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। गांव के वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि पहले पानी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था। गर्मी के दिनों में स्थिति और भी कठिन हो जाती थी। कई बार परिवार के सदस्यों का काफी समय केवल पानी की व्यवस्था में ही खर्च हो जाता था। लेकिन अब नल से जल मिलने के कारण यह समस्या लगभग समाप्त हो गई है। जल जीवन मिशन ने केवल पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य ही नहीं किया है, बल्कि ग्रामीणों में जल संरक्षण और जल स्रोतों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई है। ग्राम पंचायत एवं ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से जल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन और संधारण को बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे योजना का लाभ दीर्घकाल तक मिलता रहे। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दूषित पानी से होने वाली बीमारियों की आशंका कम हुई है तथा स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्राम राहुद में आया यह परिवर्तन ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह योजना न केवल हर घर तक जल पहुंचाने का कार्य कर रही है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन को अधिक सुविधाजनक, स्वस्थ और सम्मानजनक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

बीएसपी : रिटेंशन स्कीम में रह रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप

सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने प्रेस वार्ता कर किराए में 346% वृद्धि वापस लेने की मांग की

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई इस्पात संयंत्र में हाउस रिटेंशन स्कीम के तहत रह रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रबंधन पर भेदभावपूर्ण व्यवहार और अत्यधिक किराया वृद्धि का आरोप लगाया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता कर 6 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया।

संघ के अध्यक्ष सुरेश चंद, सुमन कन्नौजे, मोहम्मद रफी, एल.के. खाड़े, प्रजापति और राजपूत ने बताया कि संयंत्र में कर्मचारियों की संख्या घटने से बड़ी संख्या में आवास सरप्लस हो गए हैं। वर्ष 2000–2003 में वित्तीय संकट से निपटने के लिए 4500 मकान हाउस लीज स्कीम के तहत 30 साल के लिए दिए गए थे। इसके बाद 2008 में सेल बोर्ड की बैठक में हाउस लीजिंग स्कीम का दूसरा चरण लाने का निर्णय हुआ था, जिसे अब तक लागू नहीं किया गया।

"32 गुना पेनल रेंट देने के बाद भी बेदखली की धमकी"

पदाधिकारियों ने कहा कि रिटेंशन स्कीम में रह रहे सेवानिवृत्त कर्मचारी सामान्य किराये का 32 गुना दंडात्मक किराया नियमित रूप से दे रहे हैं। इसके बावजूद प्रबंधन उन्हें अनधिकृत कब्जाधारी बताकर बेदखली की धमकी दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी ओर राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और अन्य तृतीय पक्ष आवंटित वर्षों से बिना दंडात्मक किराया दिए संयंत्र के आवासों में रह रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।

346% किराया वृद्धि से आर्थिक संकट

नेताओं ने बताया कि नवंबर 2025 में किराया संशोधित किया गया। तृतीय पक्ष का किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति वर्ग फुट किया गया, जबकि रिटेंशन स्कीम में रह रहे सेवानिवृत्त कर्मियों का किराया 24 रुपये प्रति वर्ग फुट कर दिया गया। यह लगभग 346 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके कारण दिसंबर 2025 से कई सेवानिवृत्त कर्मचारी संशोधित किराया देने में असमर्थ हो गए हैं। दिसंबर 2025 से बकाया पर 18 प्रतिशत ब्याज भी लगाया जा रहा है।

पदाधिकारियों ने कहा कि सांसद विजय बघेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने इस मुद्दे पर आश्वासन दिया है। उन्होंने मांग की कि सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ सम्मानजनक और न्यायसंगत व्यवहार किया जाए।

ये 6 मांगे रखीं

1. रिटेंशन स्कीम में रह रहे सेवानिवृत्त कर्मियों के खिलाफ सभी बेदखली की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए। पहले तृतीय पक्ष के अनधिकृत कब्जाधारियों पर समान कार्रवाई हो।
2. 17 नवंबर 2025 के कार्यालय आदेश से हुई किराया वृद्धि वापस ली जाए। वैकल्पिक रूप से इसे तृतीय पक्ष के बराबर किया जाए।
3. वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति को देखते हुए मानवीय आवास नियमितीकरण नीति बनाई जाए और 2008 में स्वीकृत हाउस लीजिंग स्कीम लागू की जाए।
4. सेल पेंशन और पर्क्स का बकाया 18% ब्याज सहित तत्काल भुगतान किया जाए।
5. एस्टेट कोर्ट के आदेश के अनुसार ही किराये के बिल जारी किए जाएं।
6. मुद्रीकरण नीति के तहत आवासीय क्षेत्रों को बंजर बनाकर हस्तांतरित करने के बजाय, वर्षों से रह रहे कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को उचित मूल्य पर स्वामित्व दिया जाए।

नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिली भाजपा सोशल मीडिया टीम

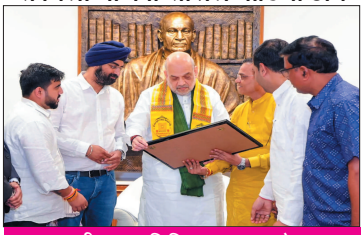

छत्तीसगढ़ डिजिटल प्रचार और जनकल्याणकारी योजनाओं पर हुई चर्चा

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मंगलवार को नई दिल्ली में भाजपा सोशल मीडिया टीम छत्तीसगढ़ ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर टीम के सदस्यों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की।

गृहमंत्री ने टीम को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के काम के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दीं। भाजपा सोशल मीडिया टीम ने छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार को और अधिक तेज करने का संकल्प भी व्यक्त किया।

रथयात्रा महोत्सव 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रथयात्रा महोत्सव 2026 में शामिल हुए। सीएम ने कहा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी जी की पावन रथयात्रा हम सभी के लिए आस्था, सेवा, समरसता और सनातन संस्कृति का महापर्व है। इस शुभ अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं देवी सुभद्रा से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करता हूँ। महाप्रभु की कृपा से हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर विकास, शांति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर रहे।

"मैं परेशान हूं" सुसाइड नोट छोड़ नगर निगम के सब इंजीनियर ने की आत्महत्या

कमरे में फंदे से लटका मिला शव, कलाई भी कटी थी

नई दृष्टिबिंदु / बिलासपुर

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक स्थित निगम कॉलोनी में बुधवार सुबह नगर निगम के सब इंजीनियर अमर सिंह चौहान का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने खुद के परेशान होने की बात लिखी है।

पुलिस के अनुसार सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को शक हुआ। दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो अमर सिंह का शव लटका हुआ था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने फांसी लगाने से पहले अपनी कलाई भी काटी थी। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है।

हाल ही में हुआ था तबादला :

अमर सिंह चौहान नगर निगम बिलासपुर में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ थे। जानकारी के मुताबिक हाल ही में उनका तबादला जगदलपुर के लिए किया गया था। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या स्थानांतरण, निजी जीवन या किसी अन्य कारण से वह मानसिक तनाव में थे।

सिविल लाइन थाना प्रभारी किशोर केंवट ने बताया कि सुसाइड नोट को जब्त कर उसकी लिखावट का सत्यापन कराया जाएगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों और सहकर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही आत्महत्या की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

GOSWWAMI
FLEX PRINTING
ADVERTIZER
भिलाई में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा
Hoardings • Flex Banner • Vinyl Printing
One Way Vision • Glow Sign Board
93290-13334, 74711-15735
goswamiflex@gmail.com
Address - 3rd Floor Shop No-1, Arora Tower, M.C. Market

अर्चना
फ्लाई ऐश ब्रिक्स
निर्माता एवं विक्रेता
हैवी इंडस्ट्रीयल एरिया, भिलाई
8 इंच एवं 9 इंच में उपलब्ध है।
संपर्क करें
9329960605, 9827160605, 9098639991

Baked by Suhani
Premium Homemade Cakes & Desserts
Birthday Cakes
Anniversary Cakes
Custom Theme Cakes
Serving Bhilai & Durg
Order Now:
@baked.by.suhani
M0.6263734520

10वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पास छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए
फायर एवं सेफ्टी प्रशिक्षण
नौकरी में सहायक
प्रवेश प्रारंभ सत्र 2026-2027
निजी कंपनियां जैसे पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत नौकरियाँ मिलती है।
प्रशिक्षण शुल्क में विशेष छूट
सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा
फायर एवं सेफ्टी प्रशिक्षण में प्रवेश प्रारंभ

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	क्र.	पाठ्यक्रम का नाम
1.	फायर टेक्नोलॉजी एण्ड इंडस्ट्रियल सेफ्टी	5.	पी. जी. कोर्स व्यावसायिक सेफ्टी, स्वास्थ्य व पर्यावरण मैनेजमेंट सिस्टम
2.	इंडस्ट्रियल सेफ्टी / पी. जी. इंडस्ट्रियल सेफ्टी	6.	हैल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर
3.	बी.एस.सी. इन फायर सेफ्टी	7.	सब- फायर ऑफिसर
4.	पी. जी. कोर्स फायर एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी	8.	सर्टिफिकेट इन फायरमैन-इंडस्ट्रियल सेफ्टी

(An Authorized Training Centre of AEERO)
फायर सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट
(मान्यता प्राप्त निजी प्रशिक्षण संस्थान)
कैंपस :- इंदिरा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़
ADMISSION HELPLINE: 7697212782

BA
BCA
BCom
BBA
BSc
PGDCA
MSc CHEMISTRY
MSc BIOTECHNOLOGY
MSc BOTANY
MSc ZOOLOGY
MSc COMPUTER Sc
MSc MATHS
MA ENGLISH
MCom
BLib
MLib
DCA
MA CHHATTISGARHI
Deepak Advertisers
Affiliated to Hemchand Yadav University, Durg
SAI COLLEGE
Street-69, Sector-6, Bhilai
70248 86996
99770 01027

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100